● वर्ष-2
● अंक-249
रायपुर, शुक्रवार
09 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

कनाडा में इंदिरा गांधी की हत्या पर जश्न

जयशंकर की दो टूक, खालिस्तानियों को जगह देना कनाडा के लिए ठीक नहीं

नई दिल्ली। कनाडा में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया, इतना ही खालिस्तानी तत्वों ने ब्रैम्पटन में वहां इंदिरा गांधी से जुड़ी झांकी भी निकाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद भारत ने गुरुवार को अलगाववादियों (खलिस्तानी) और चरमपंथी तत्वों को जगह देने के लिए कनाडा पर निशाना साधा।

एस जयशकंर ने सीधे तौर पर इस कृत्य की निंदा की और कहा कि कनाडा में भारत विरोधी तत्वों को जगह देना द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मुद्दा शामिल है। हमें वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा। वोट बैंक ही बड़ा मुद्दा है नहीं कोई ऐसा क्यों करेगा? स्पष्ट तौर एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप उनके इतिहास को देखेंगे तो आप कल्पना करेंगे कि वे इतिहास से सीखते हैं और वे उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहेंगे। यह केवल एक घटना नहीं है लेकिन यह भयानक हो सकती है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या कनाडा अपनी जमीन को खालिस्तानियों, चरमपंथियों को हिंसा की वकालत करने के लिए दे रहा है। मुझे लगता है कि यह रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है और खासतौर पर कनाडा के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है।

कनाडा का आया बयान

भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके ने ट्वीट किया कि कनाडा में नफरत या हिंसा के महिमामंडन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कनाडा में इस तरहा के

कार्यक्रम की खबरों से स्तब्ध हूं, जिसमें दिवंगत भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया। कनाडा में नफरत या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इन गतिविधियों की कड़ी निंदा करता हूं।

मुद्दा मजबूती से उठाएं : कांग्रेस

कांग्रेस ने कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए कथित तौर पर झांकी निकाले जाने की घटना की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारत सरकार को यह मुद्दा कनाडा के समक्ष मजबूती से उठाना चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह आग्रह किया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, कनाडा के ब्रेम्पटन में खालिस्तान समर्थकों ने हाल ही में इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाते हुए झांकी निकाली। इसका वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस नेता मिलिंद देवरा ने ट्वीट किया, एक भारतीय के रूप में यह देख कर मुझे पीड़ा हुई कि कनाडा के ब्रेम्पटन में पांच किलोमीटर लंबी परेड निकाली गई जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया। यह किसी का पक्ष लेने की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्र के इतिहास और पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से हुई पीड़ा के सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, चरमपंथ की सार्वभौमिक रूप से निंदा की जानी चाहिए और इसका मिलकर सामना किया जाना चाहिए। देवरा के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए रमेश ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं। यह घिनौना है। डॉक्टर जयशंकर से आग्रह करता हूं कि कनाडा के समक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाना चाहिए।

कड़ा एक्शन होना चाहिए-लेखी

विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कनाडा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते कहा कि ऐसे लोग जो हत्या का जश्न मना रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेखी ने कहा कि कनाडा सरकार को ऐसे मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कनाडा में हुए इस जश्न पर ऐतराज जताते हुए सवाल किए कि कनाडा सरकार ऐसे मामले में मौन क्यों है?

हिंदू मंदिरों को बनाया जा रहा निशाना

दरअसल कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। कनाडा में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने के भी कई मामले सामने आए हैं। इसे लेकर भारत कई बार कनाडा की सरकार के सामने आपत्ति जाहिर कर चुका है लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

अगर सीएए नहीं होता तो इन लोगों का क्या होता-विदेश मंत्री

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा में दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने अफगान सिख शरणार्थियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान से भारत आए सिखों से मिलना चाहता था और उनके मुद्दों को समझना चाहता था। उन्हें वीजा और नागरिकता को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम उन मुद्दों का समाधान करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का भी जिक्र किया जिसको लेकर देश में लंबे समय तक विरोध चला था। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अफगानिस्तान से भारत आए सिखों से मिलना चाहता था और उनके मुद्दों को समझना चाहता था। उन्हें वीजा और नागरिकता को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। हम उन मुद्दों का समाधान करेंगे जिन पर उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभी भी अपनी नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकता और वीजा को लेकर हम हर संभव मदद मुहैया कराएंगे। उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने बताया कि कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि वहां उनकी संपत्ति और गुरुद्वारे हैं उन्हें चिंता है। इस आने-जाने की व्यवस्था कैसे हो क्योंकि इसके लिए वीज़ा की दिक्क़त है। इन लोगों को डबल-ट्रिपल एंट्री वीज़ा मिलना चाहिए।

एस जयशंकर ने कहा कि कुछ लोग अपनी नागरिकता का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने बच्चों के लिए भारत की नागरिकता ली है जिसमें उनको बाद में कुछ दिक्क़तें आईं। उनको डर है कि हमारा सिस्टम आगे चलकर उनको मदद करने की जगह उन पर बोझ न डाले। यह छोटी चीज़ें आम लोगों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस क़ानून (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के कारण इन लोगों को विश्वास था कि हम आएंगे।

इन दिनों

✍ शशांक द्विवेदी

परिसीमन की आहट दक्षिण में घबराहट

भाषा और संस्कृति के रूप में दक्षिण भारत का उत्तर भारत से विरोध बहुत पुराना है किन्तु अब इसमें राजनीति का तड़का भी लगने वाला है। दरअसल, नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन के चलते संसद में दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के हिंदीभाषी राज्यों की अपेक्षा कम हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 2026 में परिसीमन किया जा सकता है। वैसे भी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या वर्तमान में अप्रासंगिक है और इसमें बढ़ोतरी समय की मांग है किन्तु यही जनसंख्या अनुपात अब दक्षिण भारत के राज्यों के लिए गले की फांस बन गया है। पिछले चार दशक में हिंदीभाषी राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर कार्य हुआ है। ऐसे में जनसंख्या अनुपात के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों में लोकसभा सीटें हिंदीभाषी राज्यों की अपेक्षा कम बढ़ेंगी। इसी कारण दक्षिण भारत के राज्यों में अभी से विरोध के स्वर प्रबल होने लगे हैं। दक्षिण भारत के नेताओं का मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य, उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों की अधिकता के बावजूद संसद में उनका प्रतिनिधित्व न बढ़ना उनके साथ अन्याय है। हालांकि संभावित परिसीमन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते। फिर अभी 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है। यदि परिसीमन आवश्यक है तो सरकार को पहले जनगणना करानी पड़ेगी। यदि 2021 की जनगणना नहीं होती है तो वह 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है किन्तु इससे भी दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय होगा। लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं के पुनर्निर्धारित कार्य को परिसीमन कहा जाता है जिसका उद्देश्य है परिवर्तित जनसंख्या का समान प्रतिनिधित्व तय करना। उक्त प्रक्रिया के चलते लोकसभा में अलग-अलग राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या तथा विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। संविधान के अनुसार किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान होना चाहिए किन्तु इसी प्रावधान के चलते जनसंख्या नियंत्रण में फिसड्डी रहने वाले उत्तर भारत के राज्यों को संसद में अधिकाधिक सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। जबकि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी सीटें कम बढ़ने का अंदेशा है। इस परिस्थिति को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर परिसीमन को वर्ष 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया था। यद्यपि लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिवर्तन पर रोक को वर्ष 2001 की जनगणना के बाद हटा दिया जाना था किन्तु पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एक अन्य संशोधन द्वारा इसे वर्ष 2026 तक के लिये स्थगित कर दिया गया। इस रोक को इस आधार पर उचित ठहराया गया कि 2026 तक देश में समान जनसंख्या अनुपात हो जाएगा जिससे दक्षिण भारत के राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के राज्यों के बराबर होगा।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रन का विशाल स्कोर बनाया हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से शानदार बल्लेबाजी हुई। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड में जबरदस्त साझेदारी कर भारत के सामने एक मजबूत चुनौती रखी है।

राहुल पर देश के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप

■ **बभाजपा नेताओं की राहुल गांधी को चिट्ठी**

नई दिल्ली। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर उनके हालिया बयानों पर आपत्ति जताई है। चिट्ठी लिखने वालों में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, परवेश साहिब सिंह और पूनम महाजन शामिल हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पर उनके अमेरिका दौरे के दौरान भारत के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि आपकी मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। सचमुच मोहब्बत में सभी को जोड़ने की भावना निहित है। इस रास्ते पर चलकर समाज और देश को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सकता है। कांग्रेस यदि इसी पॉजिटिव सोच पर चले तो कितना बेहतर हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है!

अमेरिका में आपने इस %मोहब्बत की दुकान% से अपनी मातृभूमि और देश के लिए जी-भरकर नफरत फैलाई है। वैसे नफरत फैलाना आपके परिवार और आपकी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। आप लोगों की तो इसमें महारत रही है। अपने ही परिवार के इतिहास के पन्ने पलटिए तो वो चीख-चीखकर नफरत के किस्सों की गवाही देंगे और आपके पूरे परिवार ने नफरत का मेगामॉल खोल रखा है।

लगाए गंभीर आरोप

राहुल पर निशाना साधते हुए भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर इतिहास उठाकर देखें तो आपके साथ ही हर किसी को समझ में आएगा कि आपकी मोहब्बत की दुकान की असलियत क्या है? भाजपा नेताओं ने चार दावे भी किए। पहला- कांग्रेस के राज में ही सबसे अधिक दंगे हुए और नफरत की दुकानें सजाई गईं। दूसरा- नेहरू-गांधी परिवार ने कांग्रेसी नेताओं के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की। तीसरा- आपके परिवार ने अपने ही रिश्तेदारों से किस प्रकार का अमानवीय बर्ताव किया और चौथा- देश की महान विभूतियों के प्रति आपके परिवार की नफरत आज भी प्रकट होती है। चिट्ठी में सिख दंगों के अलावा के घटनाओं का जिक्र किया गया है और इसे जायज ठहराने के लिए कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा गया है।

राहुल पर निशाना क्यों?

दरअसल, अपने अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान नाम से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा था।

प्रमुख समाचार

बौखलाए नेपाल ने अब भारतीय इलाकों पर ठोका दावा

नईदिल्ली। नए संसद भवन की एक तस्वीर लगातार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल, नए संसद भवन में अखंड भारत का एक नक्शा भी लगा हुआ है। अखंड भारत के इस नए नक्शे को देख कई देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। पड़ोसी मुल्क नेपाल भी

इस पर चितिंत हो उठा है। ऐसे में काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने जवाबी कदम के रूप में अपने कार्यालय में एक नया ग्रेटर नेपाल नक्शा रखा है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि नेपाल सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सीपीएन-यूएमएल सहित विपक्षी दलों ने उस मानचित्र का विरोध किया है जो हिमालयी राष्ट्र को प्राचीन भारतीय भूभाग के हिस्से के रूप में दिखाता है। मेयर शाह वर्तमान में अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेंगलुरु में हैं, ने अपनी भारत यात्रा से पहले मानचित्र को अपने कार्यालय में रखा था।

कोयला चोरी मामले में अभिषेक की पत्नी से ईडी की पूछताछ

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला चोरी मामले में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से करीब चार घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि

जांचकर्ताओं के पास रुजिरा से पूछताछ के लिए तीन पृष्ठों की एक प्रश्नावली थी। रुजिरा दोपहर करीब 12.40 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचीं। ईडी के एक अधिकारी ने बताया, ''उनसे विदेशी बैंकों में कुछ खातों के बारे में पूछताछ की गई। उनका बयान दर्ज किया गया।'' रुजिरा से ईडी के अधिकारियों द्वारा पूछताछ किये जाने के बारे में पूछे जाने पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, ''रहने दीजिए, यह मेरा पारिवारिक मामला है और मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहती। रुजिरा परिपक्व महिला है।

गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधन पर आरोप है कि लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया गाय। इसकी के बाद यह मामला पूरा विवादों में है और इस पर राजनीति भी हो रही है। खबरों के मुताबिक, स्कूल प्रबंधन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दमोह कांड में धर्मांतरण पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक निजी स्कूल का कथित पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर कुछ हिंदू लड़कियों को हिजाब पहने देखा जा सकता है।

ईरान ने सऊदी अरब में 7 साल बाद फिर खोला दूतावास

नईदिल्ली। ईरान ने सात साल बाद सऊदी अरब में अपने दूतावास को फिर खोल दिया। रियाद में 6 जून को यह दूतावास खुला। इसके साथ

ही खाड़ी के दो अहम देशों के बीच राजनयिक रिश्ते फिर बहाल हो गए। इस मौके पर दूतावास परिसर में समारोह भी हुआ। इसमें कई राजनयिक शामिल हुए। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि यह दिन ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों के लिए अहम है। हमें उम्मीद है कि इससे क्षेत्र स्थिरता और विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, ईरान-सऊदी अरब संबंधों में आई नरमी का पश्चिम एशियाई भू-राजनीति पर विशेष रूप से चीन द्वारा निभाई गई भूमिका के संदर्भ में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चीन स्पष्ट रूप से अमेरिकी प्रभाव वाले क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने में काफी एक्टिव था।

डिजिटल रुपये को यूपीआई के साथ जोड़ने की योजना

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्रस्तावित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के क्यूआर कोड को यूपीआई भुगतान प्रणाली के साथ

संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि केंद्रीय बैंक ने इस महीने के अंत तक ई-रुपये यानी सीबीडीसी के उपयोगकर्ताओं की संख्या को 10 लाख तक पहुंचाने की योजना भी बनाई है। इसके साथ ही शंकर ने कहा, आरबीआई ने सीबीडीसी के क्यूआर कोड को एकीकृत भुगतान प्रणाली के साथ समायोजित करने की भी योजना बनाई है। शुरुआती दौर में सीबीडीसी के थोक इस्तेमाल का परीक्षण किया गया था और बाद में खुदरा उपयोग को भी परखा गया। रिजर्व बैंक चाहता है कि लोगों के बीच भुगतान के लिए बेहद लोकप्रिय हो चुके यूपीआई मंच का इस्तेमाल वह सीबीडीसी के क्यूआर कोड के लिए भी करे।

बृजभूषण प्रकरण से महिलाओं के बीच गया गलत संदेश

अमित शर्मा

महिलाओं के लिए मोदी-योगी सरकार ने जितनी योजनाएं लागू कीं, सुरक्षा की जो गारंटी दी, इससे महिलाओं का झुकाव भाजपा की तरफ बेशक बढ़ा हो, लेकिन बृज भूषण शरण सिंह प्रकरण ने भाजपा की इस छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी तमाम पदाधिकारियों की राय है। बृज भूषण पर अभी तक कार्रवाई न होने और इस मामले को इतना लंबा खींचने से महिलाओं में खासा असंतोष है।

पार्टी के महिला मोर्चे की एक पदाधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिये महिलाओं को सशक्त करने का मजबूत कदम उठाया है। गरीब परिवारों के लिए 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण कर, हर गरीब परिवार तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस पहुंचाकर और पीएम आवास योजना के अंतर्गत मुफ्त मिल रहे घरों का महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराकर पीएम मोदी ने महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है।

इसी तरह द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय महिलाओं को सौंपकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि महिला विकास उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। लेकिन नेता के मुताबिक़, बृज भूषण शरण सिंह के मामले के कारण पूरे देश की महिला मतदाताओं के बीच एक गलत संदेश गया है। इस मामले को समय से निपटाना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि इस मामले में हुई राजनीति को महिलाएं भी करीब से देख रही हैं, और उनका

भाजपा से विश्वास नहीं डिगा है।

पहलवानों ने बृज भूषण को उखाड़ा

गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद कुश्ती पहलवानों का मुद्दा लगभग सुलझता दिखाई पड़ रहा है। सुलह का जो फॉर्मूला निकाला गया है, उसमें पहलवानों को दो कदम पीछे जरूर हटना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कुश्ती संघ पर 12 सालों से जमे ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती संघ से हमेशा के लिए बाहर कर दिया है। समझौते में पहलवानों ने कुश्ती संघ का इसी महीने चुनाव कराने और उस चुनाव से बृज भूषण शरण सिंह के परिवार को बाहर रखने की मांग की है। सरकार पहलवानों की इस मांग को स्वीकार कर सकती है, जिससे उनकी एक बड़ी मांग पूरी हो जाएगी।

चूंकि कुश्ती संघ के नियमों के मुताबिक़ कोई व्यक्ति 12 सालों से ज्यादा समय तक कुश्ती संघ का अध्यक्ष नहीं रह सकता, यह पहले से ही तय था कि ब्रज भूषण शरण सिंह इस बार चुनाव में न उतरते। लेकिन कथित तौर पर वे यह कुर्सी अपने बेटे के लिए सुरक्षित करने की चाल चल रहे थे। लेकिन पहलवानों की जिद के आगे अब उनकी यह चाह सफल होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है।

पॉक्सो में बच गया पूर्वांचल का खिलाड़ी

बृज भूषण शरण सिंह के मामले में सबसे बड़ा पेंच नाबालिग महिला पहलवान के द्वारा उनके ऊपर लगाया गया यौन शोषण का आरोप था। लेकिन जिस तरह से नाबालिग महिला पहलवान ने अपने ऊपर हुए यौन शोषण के आरोपों से किनारा कर लिया है, अदालत में यह मामला कमजोर पड़ना तय है और इसका लाभ बृज भूषण सिंह को मिलेगा। अब बृज भूषण सिंह अदालत में अपने बचाव में इसे राजनीति और कुश्ती संघ पर कब्जे के लिए हुई लड़ाई में आरोप करार दे सकेंगे और पॉक्सो मामले में उनके बचने की राह आसान हो सकती है। इससे एक हाथ कुछ पाते हुए भी उनके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा।

पाली तानाखार एवं कोरबा विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन हुई

■ पाली में दर्जनों महिलाओं ने किया भाजपा प्रवेश

कोरबा। केंद्र सरकार में मोदी सरकार के बेमिसाल 9 वर्ष पूर्ण होने कर विभिन्न आयोजन कर रही है, जिसके माध्यम से भाजपा जन-जन तक पहुंचने की योजना बना रहीं है साथ ही केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश हित में किए गए अतुलनीय कार्यों से लोगों को अवगत करा रही है।

इसी कड़ी में पाली तानाखार की विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मेलन पाली हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया। जिसमे विधानसभा के पांचों मंडल पाली, चैतमा,चोटिया,पसान एवं पोड़ी उपरोड़ा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। वही कोरबा विधानसभा के संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन दीनदयाल कुंज, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया। जिसमें कोरबा विधानसभा अंतर्गत आने वाले 5 मंडल कोरबा, कोसाबाड़ी, बालको, दर्री एवं बांकी मोगरा मंडल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

मंच पर उपस्थित अतिथियों ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरा, साथ ही प्रदेश की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया, साथ ही साथ केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में 30 मई से 30 जून तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के योजना बना कार्यों का विभक्तिकरण किया गया ।

पाली विधानसभा के आयोजन के दौरान चोटिया मंडल के दर्जनों महिलाओं से भाजपा के रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा प्रवेश किया।

पाली के आयोजन के अवसर पर प्रमुख

रूप से राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ज्योतिनंद दुबे,जिला संगठन सह प्रभारी गोपाल साहू,पूर्व महापौर जोगेश लाम्बा,विधानसभा संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष संजय भावनानी, जिला मंत्री अजय जायसवाल,आदिवासी मोर्चा प्रदेश सदस्य श्याम लाल मरावी,किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कीर्ति कश्यप,चोटिया मंडल प्रभारी संजय शर्मा,आदिवासी मोर्चा जिला महामंत्री विजय बहादुर जगत,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवी सिंह टेकाम,आदिवासी मोर्चा जिला मंत्री शिव प्रकाश कंवर,जिला पंचायत सदस्य रामनारायण उरेती,पूर्व सदस्य राज्य युवा आयोग रघुराज सिंह उईके,गोवर्धन कंवर,पाली भाजपा मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर,पसान भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन पोया,मंडल अध्यक्ष रवि मरकाम, चैतमा मंडल अध्यक्ष कृष्णा यदु,रघुनंदन जायसवाल,महामंत्री विवेक कौशिक,कमल सिंह राज,भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश कौशिक,महिला मोर्चा अध्यक्ष चैतमा चंद्रमति यादव,विधानसभा मीडिया प्रभारी भाजपा दीपक शर्मा,विधानसभा मीडिया सह प्रभारी विक्की अग्रवाल,भाजयुमो मंडल अध्यक्ष पाली दिलीप पटेल, चैतमा भाजयुमो अध्यक्ष बृजेश यादव,पोड़ी उपरोड़ा भाजयुमो मंडल अध्यक्ष मनोज डिकसेना,अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल अध्यक्ष गुरुदयाल सिंह गंभीर,शक्ति केंद्र संयोजक संतोष दास सहित बड़ी संख्या में भाजपा के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा के आयोजन के अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष लखन लाल देवांगन, जिला अध्यक्ष डॉ राजीव सिंह, कार्यक्रम प्रभारी जोगेश लांबा, जिला संगठन सह प्रभारी गोपाल साहू, जिला महामंत्री संतोष देवांगन, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी, विधानसभा संयोजक डॉ.आलोक सिंह, नेता प्रतिपक्ष हीतानंद अग्रवाल, प्रदेश मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा रितु चौरसिया, कोरबा विधानसभा विस्तारक जीवन पटेल, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, प्रदेश सदस्य आई.टी सेल लक्की नंदा, जिला संयोजक आईटी सेल अजय चंद्रा, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा पंकज सोनी, जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा अनिरुद्ध चंद्रा, जिलाध्यक्ष अजजा मोर्चा सरजू अजय, जिला अध्यक्ष महिलामोर्चा वैशाली रत्नपारखी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा संजू देवी राजपूत सहित बड़ी संख्या में भाजपा के समस्त मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने खोला मोर्चा, निकाली रैली

कोरबा। भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई के द्वारा स्थानीय पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के निदान किए जाने को लेकर आमसभा एवं रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे बालको रोड, आईटीआई चौक रामपुर कोरबा में आम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री राधेश्याम जायसवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण मंच प्रभारी लक्ष्मण चंद्रा, भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दिलीप कुमार यादव व हेतराम कर्ष विशेष रुप से उपस्थित रहे। आमसभा एवं ज्ञापन कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ कोरबा के जिला अध्यक्ष शरद नायर के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री नवरतन बरेठ द्वारा किया गया।

आम सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि आज विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गंभीर समस्या बनी हुई है। प्रदूषण के कारण मनुष्य कई प्रकार के गंभीर समस्याओं से जूझता रहता है। शारीरिक एवं मानसिक बीमारी का प्रमुख कारण है। प्रदूषण के कारण जलवायु में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते रहता हैं। असमय वर्षा, बाढ़, तापमान में परिवर्तन, इसी पर्यावरण प्रदूषण की परिणाम है। भारतीय मजदूर संघ के द्वारा एल 20 कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत भर में जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शासनए प्रशासन को भी इस पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। यदि समय रहते शासन के द्वारा हमारी मांगों को पर अमल नहीं किया

गया तो आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर एक वृहद आंदोलन करेगी। आम सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पर्यावरण मंच के प्रभारी लक्ष्मण चंद्रा ने कहा कि भारत सरकार ने 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के सामानों के उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हैए फिर भी बाजारों एवं दुकानों में धड़ल्ले इसका उपयोग हो रहा है। अमानक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर पूर्णतरू प्रतिबंध किया जाना चाहिए। उसी प्रकार जिले में कोयला के मेगा प्रोजेक्ट से निकलने वाले धूल से वहां के कॉलोनी के लोग परेशान रहते हैं। धूल के रोकथाम हेतु तत्काल प्रशासन के द्वारा प्रबंधन को निर्देश दिया जाना चाहिए। आज उद्योग लगाने के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। अनावश्यक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए एवं साथ ही साथ अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। आम सभा को भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दिलीप कुमार यादव, बाल्को के महामंत्री हरीश सोनवानी, अखिल भारतीय खनिज धातु महासंघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, भारतीय कोयला खदान मजदूर संगठन के हिरण कुमार चंद्रा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के महामंत्री अंजलि पटेल ने भी संबोधित किया।

अनियमित कर्मचारियों ने निकाली रैली बघेल सरकार को दी चेतावनी

बालोद। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले प्रदेश के 33 जिलों से रथ यात्रा निकली हुई है और इस यात्रा की शुरुआत जांजगीर जिले के शिवरीनारायण से 15 मई को हुई थी। आज यह नियमितीकरण रथ बालोद पहुंची तो नियमितीकरण की मांग को हवा मिली तो सैंकड़ों की संख्या में बालोद नया बस स्टैंड में अनियमित कर्मचारी पहुंचे हैं। सरकार को जमकर कोसा। संविदा कर्मचारी ओपी साहू जो की मनरेगा के सहायक कार्यक्रम अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि संविदा हमे कहते हैं पर असल में संविदा तो वो सरकारें हैं जो 5 साल के लिए आती हैं, उन्हें नियमित सरकार में रहना है तो हमें नियमित करना होगा। अनियमित कर्मचारियों ने शहर में रथ के साथ रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था वादा

महासंघ के बालोद जिले के सचिव रितेश गंगबेर ने बताया कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र बनाकर हम सभी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया था। इसके बाद चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। कर्मचारी प्रवीण ठाकुर और तोमन आरदा ने कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 फरवरी 2019 को कर्मचारियों के मंच पर आकर यह घोषणा की थी कि यह वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष आप कर्मचारियों का होगा। लेकिन आज तक इस बात पर कभी अमल नहीं किया गया। ओपी साहू ने कहा सरकारें सब के लिए कर रही हैं तो हमने क्या किया है। अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो हम अनिश्चित कालीन हड़ताल करने पर उतारू हो जायेंगे।

बालोद जिले के प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष देवलाल ठाकुर अनियमित कर्मचारियों का समर्थन देने उनके मंच पर पहुंचे। इस दौरान देवलाल ठाकुर ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में जब घोषणा पत्र बनाने की बात आई तो सिंह देव जी बालोद आए थे। उसी समय मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था। मैंने देखा है कि एक नियमित कर्मचारियों के बराबर और उससे ज्यादा आप सब काम करते हैं। आपने कभी खुद से नियमित कारण नहीं मांगा था। यह सरकार का वादा था। सभी से राय लेकर घोषणा पत्र बनाया गया था और आपकी ही बदौलत सरकार सट्टा संचालित है और सरकार को तो आप सभी की मांगों को पूरा करना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि अब सरकार आपके हाथ में है। आने वाला समय चुनाव की तारीखों का है। आपको भी अपने होने का एहसास सरकार को कराना होगा। उनके साथ वरिष्ठ आदिवासी नेता शरद ठाकुर भी मौजूद रहे।

हाथियों के उत्पात को देखने अब होगी ऑनलाइन निगरानी

■ सिहावा विधायक ने हाथी ट्रैपिंग एवं अलर्ट एप किया लांच

नगरी। छत्तीसगढ़ में पहली बार हाथी ट्रैपिंग एवं अलर्ट ऐप लॉन्च वन विभाग द्वारा किया गया है। यह एप जनहानि रोकने के साथ जानवरों की सुरक्षा पर काम करेगा। धमतरी जिले के सीतानदी अभ्यारण्य के ग्राम मेचका में कार्यक्रम आयोजित कर इस ऐप्लीकेशन को सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव और डीएफओ वरूण जैन ने लॉन्च किया। बता दे कि यह एप 20 किमी के दायरे में मौजूद हाथी या उसके झुंड आने पर मोबाईल में मैसेज भेज देगा।

दरअसल धमतरी जिले में कुछ सालो से हाथियों का आना जाना लगा हुआ है और बीते तीन से चार सालो में हाथियों ने दर्जन भर से ज्यादा लोगो की जान ले ली है इसके साथ ही भारी मात्रा में फसलों और घरों को हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। धमतरी जिले में लोग हाथियों की दहशत में जीने को मजबूर है जिसको देखते हुए वन विभाग द्वारा हाथियों से होने वाले जान माल के नुकसान को रोकने के लिए एलीफेंट अलर्ट ऐप बनाया गया है। गौरतलब है कि हाथी मित्र दल की ओर से एप्लीकेशन में हाथी सहित अन्य जानवरों का लोकेशन के साथ फोटो सब्मिट कर सर्वर में अपलोड किया गया है वही नेटवर्क नहीं है तो ऑफ्लाइन मोड पर भी काम करेगा। इसके बाद नेटवर्क पकड़ते ही तुरंत सर्वर तक फेटो पहुंच जाएगी। बता दे कि कई लोग हमेशा मैसेज नहीं देखते... इसलिए फोन के जरिए उन्हें बताया जाएगा कि हिंसक हाथी आपके एरिया से कितनी दूरी पर मौजूद है। वही

सीतानदी-उदंती अभ्यारण्य के गांवों में ग्रामीण, सरपंच-उपसरपंच, कोटवारो को इस एप से जोड़ा गया है.....हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगो का कहना है कि उन्हे हाथियों से हर पल खतरा रहता है ऐसे में एलीफेंट अलर्ट ऐप उनकी बहुत काम आयेगी विधायक का कहना है कि इस एप से क्षेत्र के लोगो को काफी फायदा मिलेगा.....साथ ही जान माल की नुकसान को भी समय रहते बचाया जा सकता है।

धमतरी जिले के जंगलो में चारा पानी पर्याप्त मात्रा में होने के कारण से यंहा सिकासेर दल,चंदा हाथी का दल की मौजूदगी बारहो माह देखने को मिलती है....वही इन हाथियों के कारण से जान माल को काफी नुकसान हो रहा है....बहरहाल वन विभाग व्दारा तैयार एलीफेंट अलर्ट ऐप हो रहे नुकसान को रोकने में काफी कारगार साबित होगा.....

वही हाथी एप लॉन्च कार्यक्रम मे पर्यटक जिप्सी का उद्घाटन विधायक द्वारा किया गया साथ ही वन विभाग द्वारा उदन्ती सीतानदी मे मौजूद पक्षियो का बुक के साथ सीतानदी की विस्तृत जानकारी का बुक का विमोचन कर ग्रामीणो को दूरबीन व टार्च भी वितरण किया गया जहा पर्यटक के लिये जंगलो मे घूमने जिप्सी व नाविक बोट की भी सुविधा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नवतपा बीतने के बाद भी तपा रही सूरज की धूप

कोरबा। नवतपा बीतने के पांच दिन बाद भी सूरज की धूप के तेवर कम नहीं हुए हैं। बुधवार को दोपहर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सुबह से चढ़ती धूप से हलकान लोग अब बेसब्री से मानसून का इंतजार करने लगे है। आषाढ़ माह की शुरूआत हो चुकी हैं। इसके बाद भी ग्रीष्म का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब भी तरह.तरह की जतन कर रहे हैं। दोपहर के समय सड़कों में आना जाना थम जाता है। लोग चेहरे पर स्कार्फबांध कर सफर करने को मजबूर हैं। दोपहर के समय तापमान शीर्ष पर होने से लू लगने का भय बना हुआ है। ग्रीष्म के असर से शीतल पेय सामाग्रियों की मांग अब भी बनी हुई है। जिला चिकित्सा विभाग की ओर से बदलते मौसम के साथ होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए एलर्ट किया गया। तपती धूप की वजह भूमिगत जल स्त्रोत 15 से 20 मीटर नीचे चला गया है। कालरी क्षेत्र में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। आम तौर मानसून आगमन का संकेत 15 जून के बाद शुरू होती है।

जिनके घर में नहीं है शौचालय पंचायत में आवेदन करें

बीजापुर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त समुदायों का निर्माण एवं उनका स्थायित्व बनाये रखने 1 जून से 15 अगस्त तक के दौरान घर-घर शौचालय अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर राजेन्द्र कटारा ने जिले के सभी ग्राम पंचायतों, ग्रामों में शौचालय विहिन परिवारों के आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से या पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के माध्यम से शौचालय के लिए आवेदन कराने के निर्देशित किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रवि साहू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत शौचालय विहिन परिवार जिनको पूर्व में किसी भी योजना से शौचालय का लाभ नहीं मिला है आवेदन कर सकतें है। राज्य कार्यालय से घर-घर शौचालय अभियान हेतु रूपरेखा तैयार किया गया है जिसमें 15 जून 2023 तक ग्रामीण परिवारों से अभियान की समयबध्दता को दृष्टिगत रखते हुए निर्माण के लिए आवेदनों के साथ आवेदको से समय सीमा में शौचलय निर्माण पूर्ण करने स्वीकृति पत्र लिया जाना है।

शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 जून को, 14 परीक्षा केंद्र निर्धारित

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 10 जून 2023 को किया गया है।प्रथम पाली में पूर्वान्ह 9 से 12:15 बजे तक शिक्षक एवं द्वितीय पाली में अपरान्ह 2 बजे से 5:15 बजे तक सहायक शिक्षक हेतु भर्ती परीक्षा होगी । दोनो पालियों के लिए जिले में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदाबाजार, शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय बलौदाबाजार, पंडित चक्रपाणि शुक्ला शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार, पंडित लक्ष्मी प्रसाद तिवारी शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार, गुरुकुल अंग्रेजी माध्यम उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार,स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बलौदाबाजार, सरस्वती शिशु मंदिर बलौदाबाजार, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सकरी आदि को परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं।

चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण को लेकर हँगामा

जशपुर। चंगाई सभा के आड़ मे हिन्दुओ को ईसाई बनाने का आरोप लगाते हुए, हिन्दू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओ ने जम कर बवाल काटा। सुचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पांच आरोपितो को गिरफ्तार किया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बालाछापर की है जानकारी के अनुसार शहर के समीपस्थ ग्राम बाला छापर के स्कुलडीपा बस्ती मे हीरामुनी बाई के घर मे चंगाई सभा का आयोजन कर, हिन्दुओ को ईसाई धर्म मे मतांतरित कराने की सूचना मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनी भगत, गंगा राम भगत, अरविन्द भगत, दुर्गादेवी, हिन्दू वाहिनी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। सबने मिल कर, चंगाई सभा स्थल को घर लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष रायमुनी भगत ने बताया की जिस समय वे बाला छापर पहुँचे, हीरामुनी बाई के घर मे 50 से 60 लोग जमा थे। एक टेबल मे ईसाई धर्म के देवी देवताओ के चित्र के साथ पूजा समान रखा हुआ था। वहाँ पर जमा कुछ लोग, प्रार्थना और अभिमंत्रित जल से बिमारी का इलाज करने का झांसा, स्थानीय लोगो को दे रहे थे।

राइस मिल के पास भीषण सड़क हादसा

बालोद। बालोद जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर ग्राम चिटौद के पास बरडिया राइस मिल पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना इतनी भायनक थी कि युवक के शरीर के चीथड़े उड़ गए थे। यह घटना अज्ञात वाहन के कुचलने से हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुरूर थाना प्रभारी अरुण कुमार साहू ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद मृतक की शिनाख्त एक शिक्षक के रूप में हुई है। थाना प्रभारी अरुण कुमार साहू ने बताया कि मृतक की पहचान श्रवण कुमार ठाकुर पिता केजू राम ठाकुर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम मोखा थाना भखारा के रूप में की गई है। वह केशकाल विकासखंड के ग्राम बनिया गांव में शिक्षक के रूप में पदस्थ था। वर्तमान में मृतक गुजराती कॉलोनी धमतरी में रहता था। दुर्घटना के बाद परिजनों को इसकी सूचना दी गई। पंचनामा किया गया है। शव का पोस्टमार्टम किया गया है। थाने में मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है।

विधायक ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरण किया नगद भुगतान

■ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्णय से 54 हज़ार से अधिक संग्राहकों को अपने गाँवों में ही मिल रहा है तेंदूपत्ता का नगद भुगतान

■ जिले में 32 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों में हो रहा है वितरण

बीजापुर। बीजापुर के विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी ने बुधवार को ग्राम कर्रेमरका, माटवाडा, जांगला, बरदेला, जैवारम और मिंगाचल फड़ों के तेंदूपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान का वितरण किया है। कई पल ऐसे आए जब विधायक के हाथों तेंदूपत्ता संग्राहक नगद भुगतान प्राप्त कर भावुक हुए, तेंदूपत्ता संग्राहकों में किसी ने 32 हज़ार तो किसी ने 28 हज़ार, किसी ने 27 हज़ार, किसी ने 20 हज़ार, 19हज़ार, 18 हज़ार तो किसी ने

15 हज़ार रूपयों से अधिक की राशि तेंदूपत्ता संग्रहण कर प्राप्त किए हैं जिसका भुगतान जिले भर के तेंदूपत्ता फड़ों में तेंदूपत्ता संग्राहकों को किया जा रहा है।

विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदूपत्ता आय अर्जित करने का एक प्रमुख साधन है, बीजापुर ज़िले के तेंदूपत्ता संग्राहको की माँग थी कि संग्राहकों के भुगतान बैंक अकाउंट से न करवाकर सीधे उनके गाँव में ही नगद भुगतान किया जाये, इस माँग को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गम्भीरता से लिया और बीजापुर जिले के तेंदूपत्ता संग्राहक को नगद भुगतान किए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया अब संग्राहकों को नगद भुगतान किया जा रहा हैं नगद भुगतान पाकर तेंदूपत्ता संग्राहक खुश है। इस दौरान विधायक विक्रम मंडावी ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से वार्तालाप भी किया और गाँव की समस्याओं को सुना। एक जानकारी के अनुसार बीजापुर ज़िले को तेंदूपत्ता सीजन 2023 के लिए 28 समितियों बाँटा गया है जिसके अन्तर्गत 465 फड़ों में 54 हज़ार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों ने कुल 81098 मानक बोरा से अधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण लगभग सात दिनों में किया जिसका कुल भुगतान बत्तीस करोड़ तिरालिस लाख तिरानब्बे हज़ार आठ सौ अट्ठाइस रुपये होता है जिसे तेंदूपत्ता संग्रहितों को वितरण किया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनियमित कर्मचारी तरस रहे है वेतन के लिए

बालोद। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू ने बताया कि प्रदेश के सभी अनियमित कर्मचारी प्लेसमेंट, संविदा, दैनिक वेतन भोगी, ठेका, मानदेय, श्रमायुक्त, जॉबदर कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार संघर्षरत है। 08.05.2023 को मुख्यमंत्री, निज सचिव, मंत्री, सचिव एवं संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कलेक्टर बालोद के माध्यम से संचालक के नाम वेतन वृद्धि के संबंध में पत्र लिखा गया था। दिनांक 30.05.2023 को जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संचालक को वेतन वृद्धि के संबंध में पत्र प्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान स्तिथि में पूरे प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सखी सेंटर में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों का वेतन विगत 5 महीनो से नहीं मिला है। प्रदेश के सभी सखी सेंटर में केंद्र प्रशासक, प्रमर्शदाता, केसवर्कर, आईटी वर्कर, बहुउद्देशीय सहायक के पदों पर कार्य करते है। एक तरफ 2017 से वेतन वृद्धि नहीं करना वही दूसरी तरफइन अनियमित कर्मचारियों को विगत 5 महीनो से वेतन न मिलना इन अनियमित कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं पूरी तरह से अन्याय हो रहा है वही दूसरी तरफ आर्थित शोषण के शिकार भी हो रहे है। विभाग के अधिकारी भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे है और क्यों ध्यान देंगे क्योंकि अधिकारियों को समय पर हर महीना वेतन मिल जाता है, हर साल वेतन वृद्धि होता है शासन द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ता मिल जाता है सभी सुविधाओं का लाभ समय पर मिल जाता है ऐसे में इन गरीब,किसान,मजदूर के बच्चे जो अनियमित कर्मचारी है उनके बारे में इनकी समस्याओं को सुनने वाले भी नहीं है।

23 साल बाद भी समस्या नहीं हुई दूर

छत्तीसगढ़ को बने 23 साल होने वाला बड़े बड़े अधिकारी आए बड़े बड़े नेता बने लेकिन गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो अनियमित नौकरी कर रहे है अनेक विभागो में इनकी समस्याएं जस का तस बना हुआ है। सरकार न्याय की बात करती है क्या अनियमित कर्मचारियों को न्याय दिला पाएगी। अक्सर अधिकारी बजट का हवाला देते है क्या बजट के लिए अधिकारी पत्र लिखे होंगे यह सोचनीय है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

ममता बनर्जी ने मोदी को भेजे बंगाल के खास किस्म के आम

कोलकाता। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के आमों की शीर्ष किस्मों को भेजा है।

सीएम बनर्जी ने केंद्र सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद कई सालों से पीएम मोदी को आम भेजने की परंपरा को कायम रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री कार्यालय को आम भेजे हैं। सूत्र ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को भी यह भेजा गया है। सीएम ममता बनर्जी के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि आमों को डिस्पैच मंगलवार शाम को किया गया। नबन्ना के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्तों के तहत बताया कि हिमसागर, लक्ष्मणभोग और फाजली सहित चार किलोग्राम विभिन्न किस्मों के आमों को प्रधानमंत्री आवास 7, लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में एक सुंदर उपहार बॉक्स में भेजा गया है।

राहुल की मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर स्मृति का तंज

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं और अक्सर अपने इस बयान के जरिए भाजपा को निशाने पर लेते रहते हैं। अब भाजपा ने भी राहुल को निशाने पर ले लिया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें राजस्थान में महिलाओं के अपहरण की बात शामिल है? हिंदू जीवन शैली का अपमान शामिल है? भारत को अस्थिर करने वालों के साथ सहयोग शामिल है? या फिर बाहर जाकर हमारे लोकतंत्र में दखल देने की मांग शामिल है? स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी सियासत से है?

जब केजरीवाल के सामने लगे मोदी-मोदी के नारे

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को संयुक्त रूप से गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी दिल्ली परिसर का उद्घाटन किया। इसी दौरान जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना संबोधन दे रहे थे तभी मोदी, मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। मामले को लेकर सत्तारूढ़ आप ने भाजपा पर कार्यक्रम में हंगामा करने का आरोप लगाया है। उन्हें बाधित करने वालों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इस तरह के नारे लगाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है तो यह पिछले 70 वर्षों में हो गया होता। अपने संबोधन के दौरान, केजरीवाल दिल्ली सरकार के स्कूली शिक्षा मॉडल के बारे में बोल रहे थे, तभी दर्शकों के एक वर्ग ने मोदी, मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा मुझे पता है कि आपको मेरे विचार पसंद नहीं आ सकते हैं। आप टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन यह सही नहीं है।

राजस्थान में कानून व्यवस्था अच्छी: अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अभी से ही सक्रिय हो गए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रही है। तो दूसरी ओर लगातार भाजपा राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। इस बीच एक बार फिर से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में कानून व्यवस्था का दावा किया है और साथ ही साथ कहा है कि वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि आगामी चुनाव में किसी तरह की अप्रिय घटना राजस्थान में ना हो पाए। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों में जो योजनाएं शुरू की हैं, उनसे राज्य के लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संजीवनी घोटाले के आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए एक साल से प्रवर्तन निदेशालय से गुहार लगा रही है लेकिन उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई।

समीर वानखेडे की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक 23 तक बढ़ी

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने उगाही और रिश्वत के एक मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेडे की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की अवधि को 23 जून तक के लिए बढ़ा दिया। वानखेडे के खिलाफ यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज किया है। मामले के अनुसार वानखेडे तथा चार अन्य आरोपियों ने अक्टूबर 2021 को क्रूज पोत में कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामद होने के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के एवज में अभिनेता से 25 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी दीगे की खंडपीठ ने कहा कि वह सीबीआई की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज करने संबंधी वानखेडे की याचिका पर 23 जून को सुनवाई करेगी। वानखेडे ने मामले को रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पिछले महीने उच्च न्यायालय में दाखिल की थी।

दुनिया में बढ़ी भारत की ताकत, राहुल पर बोले विदेश मंत्री

देश की राजनीति को बाहर ले जाना गलत: जयशंकर

नईदिल्ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक विकास भागीदार के रूप में देखता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा कि आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव भी तेज होगा। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हम कोविड के दौरान फंसे हुए कम से कम 70 लाख लोगों को वापस लाए।

जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी (राहुल गांधी) आदत है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वे देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं और चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी। उन्होंने कहा कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा परिवर्तन तो नहीं आना चाहिए...हमें पता है कि 2024 के चुनाव का नतीजा तो वही होगा। विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश की राजनीति को बाहर ले जाना गलत है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हम बाहर जाते हैं और भारत की ओर से लोगों से मिलते हैं। हम समाज के विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। दुनिया, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ, भारत को एक विकास के भागीदार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक विकास भागीदार के रूप में देखता है, न केवल एक विकास भागीदार के रूप में बल्कि एक विकास भागीदार के रूप में जो प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों पर खरा उतरता है। इसके साथ ही उन्होंनो दावा किया कि हम अपने पार्टनर के साथ वो काम करते हैं जो उनकी प्राथमिकता होती है...आज भारत की दूसरी छवि एक आर्थिक सहयोगी की है।

जयशंकर ने कहा कि आज लोग भारत को सुनना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भारत के साथ काम करने से उनका प्रभाव भी तेज होगा। आज हम जो प्रभाव डाल रहे हैं, उससे हमारी परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम पहले जी20 अध्यक्ष हैं जिन्होंने अन्य लोगों से परामर्श करने का प्रयास किया और 125 देशों ने प्रतिक्रिया दी क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है। विदेश मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान बहुत से देशों ने अपने नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हम कोविड के दौरान फंसे हुए कम से कम 70 लाख लोगों को वापस लाए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है, जिसे दुनिया ने भी माना है। जयशंकर ने उत्तरी सीमा पर स्थिति और 'बेल्ट एंड रोड' पहल के खिलाफ देश के रुख का हवाला देते हुए कहा कि भारत किसी दबाव में नहीं आता।

कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दिया जवाब

कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने एक बयान में आरोप लगाया था कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ही अंदाज में कनाडा की एनएसए को जवाब दिया है। दरअसल एस जयशंकर से कनाडा की एनएसए के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उनका बयान सुनकर मुझे हिंदी की एक कहावत याद आ रही है... उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

एनसीपी चीफ शरद पवार ने राजनीतिक दलों को दी नसीहत

चुनाव सिर्फ वहीं से लड़ें जहां से जीत पक्की हो : पवार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि वर्तमान में बीजेपी विरोधी लहर है और देश के लोग कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनावों के परिणामों को देखते हुए बदलाव चाहते हैं। पवार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर लोगों की यह मानसिकता जारी रहती है तो देश आगामी चुनावों में बदलाव देखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में छोटी-छोटी घटनाओं को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जहां कांग्रेस पांच साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापस आई।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राजनीतिक दलों को पहले आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनकी जीतने की क्षमता है, लेकिन उनके मैदान में होने से सत्तारूढ़ दलों को मदद नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया। यह पूछे जाने पर कि कोई भी राजनीतिक दल राज्य के हर हिस्से में चुनाव लड़ने की स्थिति में क्यों नहीं है और क्या यह पार्टियों के कमजोर होने का संकेत है, राकांपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टियां किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों वे ऐसा कर रहे हैं। पवार ने कहा कि पार्टियों को पहले ये देखना चाहिए कि सीटों पर चुनाव लड़कर वे सत्तारूढ़ दलों की मदद तो नहीं कर रहे हैं।

शरद पवार ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए सत्तारूढ़ सरकार को जिम्मेदार ठहराया और सभी हिंसा और सड़कों पर उतरने की गतिविधियों को विचारधारा द्वारा समर्थित बताया। छत्रपति संभाजीनगर में संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने अहमदनगर और कोल्हापुर जिलों में सांप्रदायिक झड़पों की घटनाओं, खासकर ताजा हिंसा भड़कने पर चिंता व्यक्त जताई।

पटना में विपक्षी नेताओं के महाजुटान में शामिल होंगे शरद पवार

मुंबई। बिहार की राजधानी पटना में केंद्र में सत्तासीन भाजपा को पटखनी देने के लिए विपक्षी नेताओं के महाजुटान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल होंगे। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने की रणनीति तैयार की जाएगी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को मुंबई में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को लामबंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। वहीं, पटना में जदयू के एक नेता ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की यह बैठक पटना में 23 जून को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। उन्होंने फोन पर मुझे इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है। नीतीश कुमार ने देश के तमाम विपक्षी नेताओं को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। शरद पवार ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय मुद्दे पर एक साथ काम करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह बैठक बुलाई है।

विपक्षी दलों की बैठक पर तेजस्वी बोले- डर गई है भाजपा, पलटवार में भगवा पार्टी ने कहा- 2024 में भागलपुर पुल की तरह बह जाएंगे

पटना। 2024 चुनाव में महज एक साल से भी कम का वक्त बचा है। इसको लेकर अब रणनीति भी तैयार होने लगी है। पटना में विपक्षी दलों की 23 जून को एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसको लेकर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। भाजपा विपक्ष के बैठक पर चुटकी ले रही है। तो वही राजद और जदयू के नेताओं की ओर से भाजपा पर पलटवार किया जा रहा है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने से डरी हुई है क्योंकि उसे वहां एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा यह तय नहीं करेगी कि विपक्षी सम्मेलन का क्या असर होगा। दरअसल वह लोकसभा चुनाव का सामना करने से डरी हुई है। वह हाल में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारगयी है। उसे राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में एकके बाद एक हार दिखाई दे रही है।

भाजपा ने आगामी 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के मद्देनजर अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भले ही एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हों लेकिन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके अरमान उसी प्रकार बह जाएंगे, जिस प्रकार बिहार के भागलपुर में 1,750 करोड़ रुपये का पुल पानी में बह गया। केंद्रीय महिला एंव बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अभी 1750 करोड़ रूपये की लागत का एक पूरा ढांचा

वहां पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार बह जाएंगे, यह मेरा विश्वास है।उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के प्रमुखनीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 'एकजुट विपक्ष' की तरफदारी करते आ रहे हैं। उन्होंने पिछले साल भाजपा से नाता तोड़ लिया था। यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह 'ललन' ने बुधवार को घोषणा की थी कि विपक्षी दलों का सम्मेलन 23 जून को होगा।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत एफआईएच प्रो लीग में नीदरलैंड से 1-4 से हारा

आइंडहोवन। भारत शुरुआती बढ़त का फायदा उठाने में नाकाम रहा और उसे एफआईएच हॉकी प्रो लीग के मैच में मेजबान नीदरलैंड से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा।

भारत की तरफ से एकमात्र गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 11वें मिनट में किया। भारत को मैच में पांच पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला। बुधवार की रात को खेले गए इस मैच में नीदरलैंड की तरफ से पेपिजन रेयेंगा (17वें), बोरिस बुर्कहार्ट (40वें) और डुको टेलजेनकैंप (41वें और 58वें) ने गोल किए। ब्रिटेन में लगातार दो मैच जीत कर यहां पहुंची भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में ही बढ़त हासिल कर ली थी। भारत को 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला।

जब भारतीय टीम ने पेनल्टी कॉर्नर लिया तो नीदरलैंड के रक्षकों ने जानबूझकर फॉउल किया जिससे भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया। हरमनप्रीत ने इसे गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की। इससे इस सत्र में उनके कुल गोल की संख्या 17 पहुंच गई है। घरेलू दर्शकों के अपार समर्थन के बीच नीदरलैंड की टीम ने पेपिजन रेयेंगा के गोल से बराबरी करके शानदार वापसी की। इससे भारतीय टीम बैकफुट पर पहुंच गई जबकि नीदरलैंड ने अधिकतर समय गेंद को अपने नियंत्रण में रखा। नीदरलैंड को दूसरा क्वार्टर समाप्त होने से कुछ सेकंड पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन अमित रोहिदास के शानदार प्रयास भारत ने इसे बचा दिया। नीदरलैंड ने इसके बाद ही अपना दबदबा बनाए रखा और आक्रामक खेल दिखाया। उसे तीसरे क्वार्टर के शुरू में ही गोल करने का मौका मिला था लेकिन भारतीय गोलकीपर कृष्ण पाठक ने शानदार बचाव किया। भारत ने 35वें मिनट में दाएं छोर से हमला किया लेकिन गुरजंत सिंह गोल करने में नाकाम रहे। नीदरलैंड को 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे बुर्कहार्ट ने गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

63 हजार के पार सेंसेक्स निफ्टी 18,700 के ऊपर

नईदिल्ली। बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई है। सेंसेक्स 48.54 अंकों यानी 0.08 फीसदी की बढ़त के साथ 63,191.50 के स्तर पर शुरुआती कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 16.10 अंकों यानी 0.09फीसदी की मामूली बढ़त देखी गई, निफ्टी 18,742.50 के स्तर पर है। प्री-ओपनिंग में बाजार की चाल मिली जुली रही है। सेंसेक्स 57.08 अंक यानी 0.09 फीसदी की बढ़त के साथ 63,200.04 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 52.70 अंक यानी 0.28 फीसदी की बढ़त के साथ 18,673.70 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज यानी गुरुवार को ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत हो सकती है। एसजीएक्स निफ्टी में भी हल्की बढ़त देखने को मिली है। आज सुबह ये 18,823 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था।

रिजर्व बैंक ने रीपो रेट को 6.5 फीसदी पर कायम रखा

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रीपो को 6.5 फीसदी पर कायम रखा है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा है। वहीं चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.2 फीसदी से घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में लिए गए निर्णय की गुरुवार को जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र मजबूत तथा जुझारू बना हुआ है।' उन्होंने कहा कि एमपीसी ने रीपो दर को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखने का फैसला किया है।

सहकारी बैंक भी जल्द एनपीए को बट्टे खाते में डाल सकेंगे

नईदिल्ली। सहकारी बैंक जल्द ही गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल सकेंगे और चूककर्ताओं के साथ समझौता निपटान कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को यह बात कही। दास ने कहा कि आरबीआई ने दबाव वाली संपत्तियों के समाधान ढांचे के दायरे को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत सहकारी ऋणदाताओं सहित सभी विनियमित इकाइयां अब एनपीए का समाधान करने के लिए ''समझौता निपटान और फंसी हुई राशि को तकनीकी बट्टे खाते में डालने'' जैसे फैसले कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक फंसी हुई संपत्ति के समाधान की अनुमति केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को थी। उन्होंने कहा कि इस पर व्यापक दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। गौरतलब है कि सहकारी ऋण क्षेत्र में अक्सर उचित प्रक्रिया की कमी और हितों के टकराव की खबरें मिलती हैं।

रिजर्व बैंक ने 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 5.1 फीसदी किया

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को मामूली घटाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए यह जानकारी दी। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नीति उपायों के वांछित नतीजे मिल रहे हैं। अप्रैल की मौद्रिक समीक्षा बैठक में 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के 5.2 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया गया था। इस साल अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी के 6.4 प्रतिशत से घटकर 4.7 प्रतिशत पर आ गई है। अनुकूल आधार प्रभाव तथा तीनों प्रमुख समूहों में नरमी से मुद्रास्फीति नीचे आई है।

ओपेक देशों द्वारा तेल उत्पादन में कटौती

नरेंद्र तनेजा

भारत की अर्थव्यवस्था आज भी तेल पर निर्भर है। हमने सौर ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जा का विकास किया है, लेकिन आज भी अर्थव्यवस्था में पारंपरिक ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन- कोयला, तेल, गैस- की 80 फीसदी हिस्सेदारी है। इसलिये भारत की अर्थव्यवस्था को फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी या आम भाषा में तेल की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यही कारण है कि भारत में तेल की कीमत पर सरकार, उद्योगों के साथ मीडिया और आम लोगों की पैनी नजर रहती है, क्योंकि तेल की कीमतों से सरकार की अर्थव्यवस्था से लेकर आम आदमी की अर्थव्यस्था पर भी असर पड़ता है जो तेल, गैस या बिजली लेता है।

और भारत ही नहीं, अमेरिका समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज भी तेल की ही अर्थव्यवस्था हैं। इसलिए जब भी ओपेक की बैठक होती है, सारी दुनिया की निगाह उसी ओर चली जाती है। ओपेक 13 बड़े तेल निर्यातक देशों का एक गुट है जिसकी कोशिश रहती है कि कीमतें ऊपर रहें। इसलिए वो अक्सर यह प्रचार करते हैं कि तेल की कमी होने वाली है, तेल महंगा होने वाला है। यदि तेल थोड़ा सस्ता होता भी है, तो वो उत्पादन घटा देते हैं, जिससे जाहिर है कि कीमतें बढ़ जाती हैं।

पिछले दिनों ओपेक ने तेल की कीमतों को गिरने से रोकने के लिए तेल उत्पादन में कटौती का फैसला किया था। दरअसल, जब भी तेल की कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे जाती है, ओपेक बेचैन हो जाता है। दुनिया के 40 फीसदी तेल का उत्पादन ओपेक देश करते हैं। इनमें यदि रूस और अन्य देशों को जोड़ दें, तो 50 फीसदी उत्पादन ये ओपेक प्लस देश करते हैं, जिसमें ओपेक देशों समेत 23 देश आते हैं। ऐसे में

वो तेल के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते या करते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है।

पिछले दिनों ओपेक प्लस देशों की बैठक हुई मगर उनमें रूस की वजह से सहमति नहीं बन पायी। रूस के ऊपर यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिससे कई देशों ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे में रूस चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन करे और नये बाजार ढूंढे जिनमें भारत भी शामिल है। तो रूस अभी उत्पादन में कटौती नहीं करना चाहता। तो बैठक में सहमति नहीं बन पायी और ओपेक जो चाहता था कि तेल की कीमतें वापस 80 डॉलर प्रति बैरल हो जाएं, वह नहीं हो सका। तो आने वाले कुछ हफ्तों में तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली जायेंगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रूस तो उत्पादन नहीं ही घटायेगा, सऊदी अरब भी कहने के बावजूद उत्पादन कम नहीं करेगा। दरअसल, सऊदी अरब और रूस बाजार में अपनी हिस्सेदारी, यानी किन देशों को वे कितना तेल निर्यात करते हैं, उस पर वे समझौता नहीं करना चाहते। भारत अपनी जरूरत का 86 फीसदी तेल आयात करता है। छप्पन फीसदी गैस और घरों में जरूरी एलपीजी गैस का भी बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। इसके अलावा, कोयले का बड़ा भंडार होने के बावजूद भारत में 10 से 20 फीसदी कोयले का आयात होता है। भारत में जो 14 फीसदी तेल उत्पादन होता है, जो सरकारी कंपनी ओएनजीसी करती हो या वेदांता जैसी निजी कंपनियां, उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में वही कीमत मिलती है जो अंतरराष्ट्रीय दर होती है। रूस पहले भारत को दो फीसदी तेल भी नहीं बेचता था, आज भारत का 40 फीसदी से भी ज्यादा तेल रूस से आ रहा है। इसे लेकर ओपेक देशों, और खास तौर पर सऊदी अरब में बड़ी बेचैनी है। उन्हें लग रहा है कि भारत अगर रूस से ज्यादा तेल ले रहा है, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब, इराक और कुवैत से तेल लेना कम हो गया है। तेल की कीमतों के हिसाब से यूक्रेन युद्ध एक टर्निंग प्वाइंट था। पहले ओपेक और रूस मिलकर काम करते थे, जब मर्जी हो अपने हिसाब से कीमतें बढ़ा देते थे, अपने हिसाब से हेरफेर कर लेते थे। मगर यूक्रेन युद्ध के बाद तस्वीर बदल गयी। पहले तो तेल की कीमतें ऊपर गयीं, मगर अब वो नीचे आ रही हैं। अभी भारत, चीन और तुर्किये भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। यानी रूस पर प्रतिबंध के बावजूद तेल की आपूर्ति के सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ा।

यूएन महासभा के नए अध्यक्ष से उम्मीदें

कन्हैया त्रिपाठी

डेनिस फ्रांसिस को एक जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह यूएनजीए के 78वें सत्र का नेतृत्व और संचालन बतौर महासभा अध्यक्ष करेंगे। जैसा कि वह अपने संकल्पों- शांति, समृद्धि, प्रगति व सततता के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं, तो इससे दुनिया में यह संदेश पहुंचा है कि डेनिस फ्रांसिस अपने कार्यकाल में महासभा को बहुत ही रचनात्मक बनाने वाले हैं, जहां अमन और शांति के लिए पर्याप्त अवसर खुलेंगे। उम्मीद यह भी है कि जिन देशों के बीच संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति है, वहां और सुधार होगा और उन देशों की परिस्थितियां बदलेंगी। मानव अधिकारों का अतिक्रमण रुकेगा और शांति के स्थायित्व में अभिवृद्धि भी होगी। वर्ष 1953 में 8वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता भारत के सविनय अवज्ञा जैसे महत्त्वपूर्ण आंदोलन में जेल-यातना सहने वाली विदुषी स्वाधीनता सेनानी विजयलक्ष्मी पंडित ने की थी। उन्हें महासभा की पहली महिला अध्यक्ष होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। बेल्जियम के विदेश मंत्री पॉल-हेनरी स्पाक 16 जनवरी, 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। विजयलक्ष्मी पंडित ने महासभा के पहले अध्यक्ष की विरासत को आगे बढ़ाया, जिसे अब त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र की अध्यक्षता करते हुए आगे बढ़ाएंगे। हालांकि तब और अब में काफी फर्क आ चुका है। 75 साल बाद दुनिया में संयुक्त राष्ट्र को लेकर अनेक मत हैं। हालात बिलकुल बदल चुके हैं। यूएन-ओएचसीएचआर के उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क अपने कई वक्तव्यों में युद्ध की स्थितियों की ओर पूरी दुनिया का ध्यान खींचते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों का उच्चायोग यूक्रेन और रूस या सूडान में मानव अधिकारों के कटु सत्य पर मुखर जरूर हुआ, लेकिन स्थितियां सुधरी नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न इलाकों में मानव अधिकार आज चिंता के विषय हैं, तो उसकी सच्चाई से हम आंखें नहीं चुरा सकते। युद्ध क्षेत्रों को छोड़ दें तो भी ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में महिला मानव अधिकारों की स्थिति ज्यादा भयावह होती जा रही हैं। ऐसे में, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस के लिए यह वर्ष काफी उलझाव भरा हो सकता है, क्योंकि जब सितंबर में दुनिया भर के देश न्यूयॉर्क में एकत्रित होंगे, तो डेनिस के सामने कई सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब देना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने खुद कहा दिया कि डेनिस फ्रांसिस का कार्यकाल टकराव, जलवायु उथल-पुथल, और बढ़ती निर्धनता, खाद्य अभाव और असमानता, जैसे एक बहुत ही गहन चुनौतीपूर्ण दौर में शुरू हो रहा है, जबकि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भी पहुंच से बाहर होती जा रही है। यदि कुछ हल डेनिस फ्रांसिस निकाल पाते हैं, तो यह उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। विशेषज्ञ बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष की भूमिका विशेष महासभा सत्र के दौरान बहुत अहम होती है और डेनिस फ्रांसिस को इन पहलुओं से जूझना ही होगा। महासभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद डेनिस फ्रांसिस ने अपने बयान में कहा कि वह सार्थक संवाद के प्रोत्साहन और उसकी सुलभता को प्राथमिकता पर रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सार्वभौम घोषणापत्र के भव्य आयोजन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायोग 78वें सत्र को स्मरणीय बनाने की कोशिश कर रहा है। 17 सूत्रीय सतत विकास लक्ष्य-2030 पर भी अहम चर्चा इस सत्र में होगी। अब डेनिस फ्रांसिस की अपनी कार्यशैली और नेतृत्व पर यह निर्भर करता है कि वे इन मुद्दों को किस प्रकार गति प्रदान करते हैं। यदि डेनिस फ्रांसिस दुनिया की राय को एकात्म बनाकर सही दिशा में निर्णायक मानव कल्याण के लिए गतिशीलता प्रदान करते हैं, तो निश्चय ही उनकी यह कामयाबी होगी और पूरी दुनिया उनको सदैव सम्मान से देखेगी।

कितनी सफल होगी विपक्षी एकता की मुहिम

रमेश सर्राफ धमोरा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का एक मजबूत मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसके लिए नीतीश कुमार देश के विभिन्न क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों से मिलकर उन सबको भाजपा के विरोध में एकजुट होने के लिए तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार का प्रयास है कि मजबूत विकल्प के अभाव में पिछले नौ वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष विरोधी दलों का एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत किया जाए। ताकि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जा सके।

नीतीश कुमार ने जब से बिहार में भाजपा से गठबंधन तोड़ा है। उसके बाद से उनका पूरा प्रयास है कि भाजपा के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाकर उनकी मनमानी को रोका जाए। नीतीश कुमार इस मुहिम में कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं। नीतीश कुमार का मानना है कि पहले सभी भाजपा विरोधी दल एक मंच पर आकर चुनाव में भाजपा को हरायें। उसके बाद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। नीतीश कुमार अभी स्वयं को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से बाहर मान रहे हैं। उनका कहना है कि वह स्वयं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। चुनाव के बाद बहुमत मिलने पर सभी विरोधी दलों के नेताओं की सहमति से प्रधानमंत्री का चयन किया जाएगा।

नीतीश कुमार इस सिलसिले में बीजू जनता दल के अध्यक्ष व ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष व बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दरुमक के अध्यक्ष व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा के महासचिव डी राजा सहित कई अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं से इस संबंध में मिल कर चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर विस्तृत चर्चा हो चुकी है।

नीतीश कुमार अपनी भाजपा विरोधी मुहिम में जुटे हुए हैं। मगर उन्हें बहुत से स्थानों पर सफलता भी नहीं मिल रही है। कहने को तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनके बहुत ही पुराने घनिष्ठ मित्र हैं। मगर वह नीतीश कुमार की मुहिम में शायद ही शामिल हों। नवीन पटनायक केंद्र की भाजपा सरकार को हर मुद्दे पर साथ देते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी भी अंततः भाजपा की तरफ ही जाएंगे।

भाजपा विरोधी दलों में इस समय नीतीश कुमार ही ऐसे नेता हैं जिनके सभी दलों के नेताओं से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं तथा वह सभी से खुलकर बात कर सकते हैं। नीतीश कुमार की मुहिम में अधिकांश राजनीतिक दलों ने उनसे साथ देने का वादा भी किया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और हम सहित कई राजनीतिक दल पहले से ही नीतीश कुमार नीत गठबंधन सरकार में साथ हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और असम से सांसद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने भी नीतीश की मुहिम में शामिल होने के लिए हां कर दी है।

नीतीश कुमार अपनी भाजपा विरोधी मुहिम में जुटे हुए हैं। मगर उन्हें बहुत से स्थानों पर सफलता भी नहीं मिल रही है। कहने को तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनके बहुत ही पुराने घनिष्ठ मित्र हैं। मगर वह नीतीश कुमार की मुहिम में शायद ही शामिल हों। नवीन पटनायक केंद्र की भाजपा सरकार को हर मुद्दे पर साथ देते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी भी अंततः भाजपा की तरफ ही जाएंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव भी कांग्रेस के साथ किसी मोर्चे में शामिल होना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया है। उनका कहना है कि आने वाले चुनावों में वह कई प्रदेशों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में तेलंगाना में उनकी कांग्रेस से सीधी टक्कर है। इस कारण से उनका नीतीश कुमार के मोर्चे में शामिल होना मुश्किल लग रहा है।

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर चल रही हैं। उन्होंने अकेले ही आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसी परिस्थिति में वह ऐसे किसी मोर्चे में शामिल नहीं होगी जहां समाजवादी पार्टी व कांग्रेस शामिल हो। आम आदमी पार्टी की भी दिल्ली, पंजाब, गुजरात सहित हिंदी भाषी बेल्ट में भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस से भी सीधा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर ही अपना आधार बनाया है। जहां-जहां कांग्रेस कमजोर हुई है। वहां-वहां आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में शायद ही शामिल हो।

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में सरकार व उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ अध्यादेश जारी किया गया है। जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों से सहयोग मांग रही है। मगर आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में सहयोग देने के मसले पर कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो गया है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और पंजाब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा सहित कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की दुश्मन नंबर एक बताते हुए उसे किसी भी तरह का समर्थन नहीं देने की बात कही है। अजय माकन ने तो कहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा से मिलकर कांग्रेस को कमजोर करने में लगी हुई है। ऐसे में उन्हें किसी भी तरह का समर्थन देना आत्मघाती कदम साबित होगा।

पहले हिमाचल फिर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार प्रचार व रोड शो के उपरांत भी दोनों ही प्रदेशों में भाजपा अपनी सरकार नहीं बचा सकी थी। इससे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का मानना है की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी चुनाव में यदि विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़े तो भाजपा को आसानी से हराया जा सकता है। यदि इन प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भाजपा हार जाती है तो अगले लोकसभा चुनाव में उसका मनोबल काफी कमजोर हो जाएगा। वहीं इन प्रदेशों में जीतने से विपक्षी दलों की एकजुटता और अधिक मजबूत होगी। जिसका लाभ उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सकेगा।

नीतीश कुमार द्वारा आगामी 12 जून को पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक अचानक ही स्थगित कर दी गई है। बैठक को स्थगित करने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि अगली तिथि कि घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। आगामी बैठक में जितने अधिक विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे उतनी ही विपक्ष की राजनीति मजबूत होगी। भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को आपसी हितों व टकराव को टाल कर एकजुटता से मुकाबला करने पर ही कामयाब हो पायेंगे।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गरुडोपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

ऊर्ध्वगामी महागरुड़देव! आप सुन्दर पंखों से युक्त, अग्निदेव के सदृश गतिशील हैं। त्रिवृत स्तोम आपका शिर और गायत्र (साम) आपके नेत्र हैं। दोनों पंख के रूप में बृहत् एवं रथन्तर साम हैं, यज्ञ आपकी अन्तरात्मा, सभी छन्द आपके शरीर के अंग तथा यजु: आपका नाम है। वामदेव नामक साम आपकी देह, यज्ञायज्ञिय नामक साम आपकी पूँछ एवं धिष्ण्य स्थित अग्नि आपके खुर-नख हैं। हे गरुड़देव ! आप अग्निवत् दिव्य लोक की ओर गमन करें तथा स्वर्गलोक को प्राप्त करें।

प्राचीन काल में यह ब्रह्मविद्या अमावस्या पूर्णिमा के दिन बताई थी। तत्कारि-मत्कारि (उनकी अथवा हमारी हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित हो रहा है (संचरण कर रहा है), उसे (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष अर्थात् विषनाशक है। विष को दूषित एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने उस घातक विष को, अन्तलीन विष को, प्रणाशक विष को इन्द्र के वज्र द्वारा नष्ट कर दिया। विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने सहयोग प्रदान किया। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है।

तत्स्त्यम (अर्थात् यह बीज मन्त्र सभी प्रकार के विषों को हरण करने में समर्थ है) तुम चाहे अनन्तक के दूत हो अथवा स्वयं अनन्तक हो। तत्कारि-मत्कारि (उनकी अथवा हमारी) हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित (संचरित) हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों के लिए विष है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्ममय है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस विष को मारकर (उस) प्रणाशक विष को नष्ट कर दिया है। इस विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है।

तुम चाहे वासुकि के दूत हो अथवा स्वयं वासुकि हो। तत्कारि-मत्कारि (उनकी अथवा हमारी) हिंसा करने वाला जो विष वर्द्धित (संचरित) हो रहा है, ऐसे उस विष को (ब्रह्मविद्या) जो कि विषों की विष को दूषित, मारने, नष्ट एवं हरण करने वाली है, ऐसी वह जो स्वयं ब्रह्मरूपा है, उसने इन्द्र के वज्र द्वारा उस घातक विष को मारकर विनष्ट कर दिया है। इस विष को विनष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने भी सहयोग प्रदान किया है। (इस निमित्त) आहुति समर्पित है।

क्रमशः ...

बिरसा मुंडा हैं पृथ्वी के पिता एवं आदिवासियों के मसीहा

ललित गर्ग

'धरती आबा' यानी पृथ्वी के पिता के नाम से जाने वाले आदिवासी जनजीवन के मसीहा एवं भगवानतुल्य बिरसा मुंडा का 146वां जन्मोत्सव 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने न केवल अपनी प्रकृति, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी बल्कि आजादी की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी बेल्ट में बंगाल प्रेसीडेंसी (अब झारखंड) में आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने अनूठे कार्यों, अवदानों एवं व्यापक सोच से राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान किया, कठोर संघर्षों से लोहा लिया। बिरसा मुंडा एक युगांतरकारी शख्सियत थे, उन्होंने आदिवासी जनजीवन के कल्याण एवं उत्थान के लिये बिहार, झारखंड और ओडिशा में जननायक की पहचान बनाई। वे महान् धर्मनायक थे, तो प्रभावी समाज-सुधारक थे। वे राष्ट्रनायक थे तो जन-जन की आस्था के केन्द्र भी थे। सामाजिक न्याय, आदिवासी संस्कृति एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके अनूठे एवं विलक्षण योगदान के लिये न केवल आदिवासी जनजीवन बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति सदा उनकी ऋणी रहेगी।

भारत के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे आदिवासी नायक हैं जिन्होंने झारखंड में अपने क्रांतिकारी विचारों से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आदिवासी समाज की दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। अंग्रेजों द्वारा थोपे गए काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाल दिया। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके-सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। बिरसा जानते थे कि आदिवासी समाज में शिक्षा का अभाव है, गरीबी है, अंधविश्वास है। बलि प्रथा पर भरोसा है, हड़िया कमजोरी है, मांस-मछली पसंद करते हैं। समाज बंटा है, लोगों के झांसे में आ जाते हैं। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं, तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। इन समस्याओं के समाधान के बिना आदिवासी समाज का भला नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने एक बेहतर नायक और समाज सुधारक की भूमिका अदा की। अंग्रेजों और शोषकों के खिलाफ संघर्ष भी जारी रखा। उन्हें पता था कि बिना धर्म के सबको साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा। इसलिए बिरसा ने सभी धर्मो की अच्छाइयों से कुछ न कुछ निकाला और अपने अनुयायियों को उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। आदिवासियों का संघर्ष अट्ठारहवीं शताब्दी से आज तक चला आ रहा है। 1766 के पहाड़िया-विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे। सन् 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह 'ऊलगुलान' चला। आदिवासियों को लगातार जल-जंगल-जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे।

पीएम मोदी पर हमला, क्या सयाने हैं राहुल गांधी?

अवधेश कुमार

अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी के बयानों पर भारत में हंगामा मचना ही था। बीजेपी को तो उनके बयान पसंद नहीं ही आए, देश में भी कइयों को लगता है कि विदेश में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरी ओर, कई लोग राहुल की बातों का समर्थन भी कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि राहुल विपक्ष के नेता हैं। इसलिए वह सरकार की आलोचना करेंगे ही। फिर राहुल गांधी के इन बयानों को कैसे देखा जाए? इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले राहुल गांधी के चर्चित बयानों की कुछ खास बातों पर गौर करना चाहिए। जिस तरह आप (मुसलमानों) पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। भारत में राजनीति के जो नॉर्मल टूल थे, वे अब काम नहीं कर रहे हैं। हमें राजनीति के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों को धमकी दी जा रही है, एजेंसियों का (अपने फायदे के लिए) इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने (बीजेपी) पूरी कोशिश की कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। उन्होंने पुलिस और एजेंसियों का इस्तेमाल किया। मानहानि के लिए अधिकतम सजा पाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। मेरी सांसदी ही चली गई। मैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी पर बोल रहा था। राहुल गांधी बीजेपी के बाद केंद्र से राज्यों तक दूसरे नंबर की पार्टी के टॉप लीडर हैं। विदेशी धरती पर उनके बयानों में एक जिम्मेदार भारतीय नेता की छवि दिखनी चाहिए।

बीजेपी, संघ, नरेंद्र मोदी से उनके विरोध

को कोई अस्वाभाविक नहीं कह सकता। लेकिन राहुल के मामले में बात मोदी या सरकार विरोध तक सीमित नहीं रहती। जब वह विदेश में मुसलमानों के साथ दलितों, सिखों, आदिवासियों के विरुद्ध हिंसा और उन्हें सताए जाने की बात करते हैं तो यही मेसेज जाता है कि भारत में अभी ऐसा ही हो रहा है। इससे उन विदेशी शक्तियों की ताकत बढ़ती है, जो भारत के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पिछले महीने अमेरिका के एक आयोग ने भारत को अल्पसंख्यकों के लिए चिंताजनक देश की श्रेणी में रखने का अनुरोध किया था, जबकि भारत में ऐसी स्थिति है नहीं। क्या कांग्रेस के लोगों ने यह सोचा है कि अगर ये ताकतें अपनी रिपोर्ट में राहुल गांधी का हवाला दें और भारत को अल्पसंख्यकों को सताने वाला देश बताकर ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेंगी तो वे क्या जवाब देंगे? हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हम यहां किसी से मदद मांगने नहीं आए हैं। यह हमारी लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं। इसी तरह रूस-यूक्रेन युद्ध के मामले में उन्होंने कहा कि इस पर हमारी नीति वही है, जो मोदी सरकार की है। मगर दूसरी ओर उन्होंने भारत की ऐसी डरावनी तस्वीर पेश की, मानो यहां लोकतंत्र और संवैधानिक शासन खत्म हो गया है। फासिस्ट सोच रखने वाली सरकार काम कर रही है और मीडिया, जूडिशरी सब उसके कंट्रोल में है। मैं यहां इसके चार उदाहरण दे रहा हूं।

पहला, आम आदमी किसी से नफरत नहीं करता। किसी को मारने के बारे में नहीं सोचता। ये चंद लोग हैं जिनका सिस्टम पर कंट्रोल है। दूसरा, मीडिया और प्रचार तंत्र सरकार के हाथों में है। बीजेपी आगे के चुनाव हारने जा रही है, लेकिन भारतीय मीडिया कहेगा कि ऐसा नहीं होगा। तीसरा, बीजेपी ने संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। चौथा, संसद सदस्यता खत्म करने का ड्रामा असल में छह महीने पहले शुरू हुआ। हम संघर्ष कर रहे थे। क्या मीडिया की स्वतंत्रता केंद्र सरकार और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने खत्म कर दी है? क्या कर्नाटक इलेक्शन से पहले ज्यादातर मीडिया सर्वेक्षणों ने कांग्रेस को बीजेपी से आगे नहीं बताया था? क्या राहुल की संसद सदस्यता अडाणी के साथ सरकार की सांठगांठ का आरोप लगाने के कारण गई? इन सभी सवालों का जवाब ना में है। लेकिन राहुल की बातों से लग रहा है कि मानो कोर्ट ने सरकार से डरकर उनके खिलाफ फैसला दिया। क्या उनकी कही गई बात से विदेश में भारत की छवि खराब नहीं हो रही?

ओवरसीज कांग्रेस उनकी सार्वजनिक यात्राएं आयोजित कर रही है ताकि दुनिया में नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल को सबसे मजबूत विपक्षी नेता साबित किया जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉप्युलैरिटी विश्व के किसी भी नेता की तुलना में ज्यादा है। कांग्रेस प्रधानमंत्री की ओर से कही गई दो-तीन बातों को अपना मतलब निकालने के लिए गलत ढंग से पेश करती है।

वह गहराई से छानबीन करे तो पता चलेगा कि मोदी ने न केवल अपनी सरकार के दौरान भारत में आए बदलावों की पॉजिटिव तस्वीरें विदेशी मंच पर पेश कीं, बल्कि दुनिया की समस्याओं को लेकर भी अपनी सोच रखी। इसलिए उन्हें विजनरी लीडर माना जा रहा है। जहां तक हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी की हार का सवाल है तो पार्टी गुटबाजी की वजह से हारी है। नरेंद्र मोदी के प्रति आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर सम्मान और श्रद्धा का भाव है। राहुल गांधी, उनके रणनीतिकारों और ओवरसीज कांग्रेस के संचालकों का नरेंद्र मोदी, बीजेपी और संघ परिवार के प्रति सनातन वैर-भाव समझ में आता है लेकिन विदेश में देश की खराब छवि पेश कर और नेता को खलनायक बनाने से उन्हें इज्जत नहीं मिलेगी। उलटा इससे राहुल को कमजोर नेता ही माना जाएगा।

बापू की दिनचर्या

स्वावलंबन एवं शारीरिक श्रम

बचपन से शारीरिक श्रम के प्रति बापू की अत्यधिक रुचि थी। रूसी मनीषी। टॉलस्टॉय के सिद्धांत पढ़कर उनकी धारणा दृढ़ हो गई कि रोटी के लिए श्रम अनिवार्य है। जीवन की सार्थकता कर्म में है। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक जॉन रस्किन की %अंटु दिस लास्ट% पुस्तक ने उनको झकझोर दिया, जगा दिया। उसी दिन से शारीरिक श्रम उनके जीवन का व्रत बन गया। अपने आश्रमों के लिए जिस जीवन-पद्धति का उन्होंने विकास किया, उसमें शारीरिक श्रम और स्वावलंबन-दोनों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। मानवमात्र को अपना बंधु समझने का जो नवीन दृष्टिकोण रस्किन की कृति से उनके सामने आया, उससे उन्होंने सेवकों को परिवार का अविभाज्य अंग बनाकर रखने का निश्चय किया। जो इसके लिए अपने को तैयार न कर सके, उनको सादर छुट्टी दे दी। मनुष्यमात्र की समानता में आस्था रखनेवाले बापू के लिए अपने आश्रम में इससे भिन्न किसी अन्य मर्यादा को स्थान देना असंभव था। जोहांसवर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में सन् 1905 में बैरिस्टरी करते हुए भी बापू अपने परिवार में मि. पोलक, साथ रहनेवाले एक अन्य युवक संबंधी तथा एक अंग्रेज मित्र के साथ प्रातः छह बजे चक्की चलाते। उसे खड़े होकर चलाना पड़ता। सुबह उठकर वे यही पहला काम करते। पंद्रह मिनट में सारे परिवार का आटा तैयार हो जाता। वहाँ के टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स-आश्रम में खेती और बागवानी के साथ मकान बनाने, भोजन पकाने, प्रेस और मल-मूत्र की सफाई का काम हर आश्रमवासी के लिए अनिवार्य था। फिनिक्स आश्रम में बापू सुबह के जलपान के बाद आश्रमवासियों के साथ फावड़ा लेकर ढाई घंटे फलों के वृक्षों की क्यारियाँ गोड़ते और उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते। भारत लौटने पर कोचरब-आश्रम में सन् 1916 में सुबह सात से साढ़े दस बजे तक वे प्रायः दो बहनों की सहायता से सारी रसोई बनाते। प्रातःकाल आश्रम के छोटे-बड़े सभी व्यक्तियों को सामूहिक रसोईघर के काम में पौन या एक घंटा नियमित सेवा देने की अनिवार्यता थी इस सेवा के रूप में वे नित्य दिन के प्रथम प्रहर में निश्चित समय पर मुख्य रसोईघर में जाकर सब्जी काटते। उस समय अधिकतर बहनें उनकी सहायता में रहतीं। सुबह साढ़े चार से साढ़े पाँच बजे तक वहाँ नियमित रूप से पिसाई का उनका क्रम चलता। मल-मूत्र की सफाई, गड्ढे खोदना और उनमें मल गाड़ना, बर्तन माँजना, कुएँ से पानी निकालना और कपड़ा सीना जैसे कार्य सब लोग करते और इनमें उनका सहयोग रहता। आश्रम में अपने कपड़े स्वयं धोने के नियम की भाँति अपने जूठे बर्तन तुरंत साफ कर लेने की प्रथा थी। प्रत्येक व्यक्ति रसोईघर का एक बर्तन मजता। कभी-कभी कुछ अतिथियों को, जिनमें महिलाएँ भी होती, ऐसा करने में हिचकते देखा जाता। बापू, बा और कभी महादेव भाई उनकी हिचक समाप्त कर दिया करते। इससे उन लोगों को लज्जित होना पड़ता। कभी- कभी इसके विपरीत दृश्य देखने में आता लोगों में बर्तनों की सफाई के लिए छीना-झपटी की नौबत आ जाती। साबरमती में तंबू तानना, झोपड़ियाँ तैयार करना, कुएं के लिए जमीन खोदना, शहर से आवश्यक वस्तुएँ लाना, रोगी सेवा और कताई बुनाई जैसे काम बढ़ गए थे।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

वन मंत्री ने पांच विपत्तिग्रस्त परिवारों को 20 लाख का चेक वितरित किया

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा विधायक कवर्धा श्री मोहम्मद अकबर ने अपने कबीरधाम जिले में प्रवास के दौरान पांच विपत्तिग्रस्त परिवारों को चार-चार लाख रूपए कुल 20 लाख रूपए के चेक का वितरण किया। मंत्री श्री अकबर द्वारा इनमें आरबीसी-6-4 के तहत विकासखंड बोड़ला के ग्राम जीताटोला के श्रीमती कचरा बाई, ग्राम धनडबरा के श्रीमती गुनती बैगा, ग्राम थुहापानी के श्री सरजु तथा ग्राम मानिकपुर के श्री परदेशी और ग्राम गंडईखुर्द के जेठिया बाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी-6-4) के तहत 4-4 लाख रूपए का चेक प्रदान किया गया। वन मंत्री ने चेक वितरण करते हुए विपत्तिग्रस्त परिवार के सदस्यों से कहा कि वह इस चेक को बैंक में जमा कर राशि प्राप्त कर सकते हैं। चेक वितरण करते समय मंत्री श्री अकबर ने परिजनों से भेंट भी की और अपनी संवेदना प्रकट की।

सहायक प्रबंधक परीक्षा 13 जून को

रायपुर। व्यापमं ने राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के अंतर्गत सहायक प्रबंधक (उपार्जन), सहायक प्रबंधक (प्रक्रिया), सहायक प्रबंधक (निर्माण) और सहायक प्रबंधक (प्रबंधन) के संविदा पदों पर भर्ती का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इन पदों पर भर्ती के लिए 13 जून को परीक्षा होगी। आवेदक वेबसाइट पर बने प्रोफाइल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

कर्मचारी संघ अध्यक्ष पद का चुनाव 14 जून को

रायपुर। प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सोमवार को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची का प्रथम प्रकाशन निर्वाचन कार्यालय कर्मचारी भवन में किया गया। शासन से मान्यता प्राप्त संगठन के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय तिवारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी आलोक जाधव ने बताया कि जिले में 31 मई की स्थिति में संगठन के कुल पंजीकृत सदस्यों की संख्या 1339 है। सूची पर आपत्ति-दावा 6 जून 2023 को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक लिए जाएंगे। उसी दिन दावा-आपत्ति का निराकरण कर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। 7 जून को रायपुर जिला शाखा अध्यक्ष के उम्मीदवार द्वारा नामांकन जमा किया जाएगा। 14 जून को मतदान कराया जाएगा।

रोजगार मेला में 121 आवेदकों का प्राथमिक चयन व 24 को दिए नियुक्ति पत्र

दंतेवाड़ा। कलेक्टर विनीत नंदनवार के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज में आज रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इस रोजगार मेला में विभिन्न क्षेत्रों के 5 नियोक्ता संस्थाओं द्वारा 250 से अधिक रिक्तियां निकाली गई थी। मेले में जिले के 561 आवेदकों का पंजीयन किया गया था। जिसमें 121 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया साथ ही 24 आवेदकों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

सांसद सरोज पांडे ने किया दुर्ग के मुक्तिधाम का निरीक्षण

दुर्ग। जिसने चोरी की है वह घबराएगा, मुद्दों की कमी कहाँ हैं, अभी तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, अभी तो जवाब माँगना शुरू किया है और इतनी तिलमिलाहट क्यों है मुख्यमंत्री, बेरोज़गारी भत्ता और शराब बंदी पर जवाब तो देना ही पड़ेगा,, यह बात कही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने, आपको बता दें कि सरोज पांडे अपने समर्थकों के साथ दुर्ग के शिवनाथ नदी मुक्तिधाम का निरीक्षण करने आई थीं, उसी दौरान मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया,, यहाँ उन्होंने यह भी कहा कि एम्स हॉस्पिटल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी और आईआईटी प्रधानमंत्री मोदी की देन है, यह इस क्षेत्र के लिए सौगात है। 22 जून को गृहमंत्री अमित शाह जी का आगमन है बड़ी आमसभा को वे संबोधित करेंगे।

भाजपा का धमतरी में बुद्धिजीवी सम्मेलन, ओम माथुर होंगे शामिल

रायपुर। भाजपा का 12 जून को धमतरी में बुद्धिजीवी सम्मेलन है। इसमें धमतरी जिले अलग- अलग क्षेत्रों में काम करने वाले प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। सम्मेलन के कर्ता-धर्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन यहां पहुँच रहे हैं। सम्मेलन में डाक्टर, इंजीनियर, सीए, और कालेज के लेक्चरर, प्रोफेसर व साहित्यकार और पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है। इसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी।

रेल दुर्घटना में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही मोदी सरकार : प्रमोद कुंजाम

नगरी। जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रमोद कुंजाम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आजादी के बाद का यह दूसरा सबसे बड़ा रेल दुर्घटना पर अभी तक किसी के द्वारा न नैतिक जवाबदारी ली गयी हैं और न ही कोई राजनैतिक जवाबदारी लेने सामने आया है। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुंजाम ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 280 तक पहुंच गई। 1175 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मोदी सरकार रेल दुर्घटना मे इतनी बड़ी मौतो के बाद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहीहै। बालासोर, उड़ीसा में भयावह ट्रेन दुर्घटना को हुए चार दिन से अधिक बीत चुके है क्या मानवीय व नैतिक आधार पर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए?

एस्मा पर भड़के पटवारी, आदेश की जलाईं प्रतियां

■ कहा- हम डरने वाले नहीं, सीएम हाउस घेरने की तैयारी, जारी रहेगा आंदोलन

बालोद/बीजापुर। छत्तीसगढ़ में चल रही पटवारियों की हड़ताल के बीच भूपेश बघेल सरकार ने एस्मा लगा दिया है। इसके बाद पटवारी संघ भड़क गया है। बालोद और बीजापुर में हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने गुरुवार को एस्मा आदेश की प्रतियां जलाईं। कहा कि सरकार ने बिना बात किए ही कार्रवाई की है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। शहर के नया बस स्टैंड परिसर में धरने पर बैठे पटवारियों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। अब वे सीएम हाउस घेरने की तैयारी में हैं।

बालोद जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष लोकेश कुमार साहू ने बताया कि प्रदेश की सरकार अब दमनकारी नीतियां अपनाने पर उतारू हो गई है। यहां पर हमसे बिना कोई चर्चा किए एस्मा लगा दिया गया है। एक बार सरकार को हमसे बात तो करनी चाहिए। आखिर हम उन्हीं के ही तो कर्मचारी हैं। सरकार के इस आदेश के बाद पटवारियों में काफी आक्रोश है और हम एस्मा संबंधी आदेश की प्रतियां जला रहे हैं।

बीजापुर के पटवारी बीरा राजा बाबू ने बताया कि शासन प्रशासन की तानाशाही रवैया का विरोध करते हुए एस्मा की प्रतियां जलाई गई। उन्होंने बताया कि आंदोलन को आगे धार देने के लिए आगामी दिनों में आमरण अनशन, भूख हड़ताल व सीएम हाउस घेराव की तैयारी चल रही हैं। लेकिन अभी तारीख और दिन तय नहीं किया गया हैं। प्रांतीय निर्देश का इंतजार हैं। बीरा राजा बाबू ने बताया कि उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा।

ये हैं पटवारियों की आठ मांगें

वेतन विसंगति को दूर कर वेतन में बढ़ोत्तरी की जाए। वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन किया जाए. राजस्व निरीक्षक के कुल पदों मे 50त्न पर पटवारियों के वरिष्ठता के आधार पर और 50% पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रमोशन किया जाए. साथ ही 5 वर्ष पूर्ण कर चुके पटवारियों को राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण दिलाया जाए। संसाधन और भत्ते की मांग। स्टेशनरी भत्ते की मांग। अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता की मांग। पटवारी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक करने की मांग। मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त की जाए। बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज ना किया जाए।

सात जून से प्रभावी आदेश

23 दिन से चल रही हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की शक्तियों का प्रयोग किया है। यह आदेश सात जून से लागू किया गया है और आगामी तीन महीने के लिए प्रभावशील रहेगा। आदेश को राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है। इस बीच, पटवारी संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

पटवारी संघ के द्वारा प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान

दुर्ग। 8 सूत्रीय मांग को लेकर पटवारी संघ ने अनिश्चित कालीन हड़ताल का आयोजन किया। दरअसल, छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांग को लेकर 15 मई यानी पिछले 23 दिनों से प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर है। राजस्व पटवारी संघ की बेमियादी हड़ताल की वजह से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित पटवारियों से जुड़े सभी काम पूरी तरह से प्रभावित चल रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं इसलिए उन्हें भी वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो होनी चाहिए साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के बाद भी अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी पटवारियों का हाल-चाल जानने नहीं आया उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे।

पटवारी नहीं मान रहे हैं एस्मा, हड़ताल जारी

रायपुर। लंबे समय से हड़ताल पर बैठे पटवारी नवा रायपुर के धरना स्थल पर अभी भी डटे हुए और बुधवार को जारी एस्मा की प्रति जलाते हुए कह रहे हैं कि वे आरपार की लड़ाई लडऩे तैयार हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इधर एस्मा लगाया जाना मतलब उनका कार्य अत्यावश्यक सेवा के दायरे में आ गया है,शासकीय सेवकों की नियमावली के तहत ऐसी स्थिति में हड़ताल छोड़कर काम पर लौटना ही पड़ेगा अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासात्मक कार्रवाई हो सकती है, अब देखिए आगे होता है क्या? इधर वैकल्पिक तौर पर पटवारियों के काम को करने के लिए संभावनाएं भी तलाशा जा रहा है आरआइ व तहसीलदार वे काम करें. लेकिन वे भी काम करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कुछ उलझने तो भारी पड़ सकती है जैसे डीएससी रिकार्ड सिर्फ पटवारी के पास ही होता है। दुरुस्ती के बाद डीएससी रिकार्ड पटवारी के पास रहता है, जो कि वही कर सकते हैं। ऐसे में अगर डीएससी रिकार्ड को लाक कर तहसीलदारों को यह काम दिया जाएगा, तो नियंत्रण और पर्यवेक्षण का काम भी नहीं हो पाएगा। यानी कि तहसीलदार अपनी मर्जी से ही कार्य करेगा, फिर सही और गलत जांचने की भी संभावना नहीं रहेगी। बताया जा रहा है कि प्रदेशभर में राजस्व न्यायालयों में लगभग 1.40 लाख मामले लंबित हैं। जिसमें सर्वाधिक मामले रायपुर जिले में 8,262 मामले हैं। वहीं, 22 जिले ऐसे हैं जहां तीन हजार से ज्यादा मामले लंबित चल रहे हैं। इसके अलावा सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में हजार से भी कम मामले लंबित पड़े हुए हैं। इनके अलावा और भी कार्य प्रभावित हो रहे हैं जिस पर स्वंय मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई है।

जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, स्टाफ को दो माह से वेतन नहीं

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित मेडिकल कालेज के स्टाफ को दो माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इसमें जूनियर डॉक्टर से लेकर नर्स और आया तक 380 लोग शामिल हैं। स्टाफ का कहना है कि वेतन नहीं मिलने के कारण खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। मकान के किराये से लेकर राशन तक के लिए परेशान हैं। वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, इस संबंध में भी स्पष्ट जवाब नहीं है। हर बार पूछने पर सॉफ्टवेयर में दिक्कत कहकर घुमाया जा रहा है।

वर्तमान में डीएमएफडी के तहत वार्ड बॉय, आया की संख्या करीब 98 है, जबकि स्टाफ नर्स 30 हैं। इनको अप्रैल और मई माह का वेतन नहीं दिया गया है। कई स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, आया बाहर से आकर यहां किराए से रह रहे हैं। इसके अलावा कई स्टाफ शहर से आना जाना करते हैं। ऐसे में उन्हें रोजाना करीब 50 रुपये पेट्रोल पर खर्च करना पड़ता है। स्टाफ का कहना है कि अब किराने की दुकान में जाने पर शर्म आती है। उन्हें पहले की ही उधारी नहीं दी।

वहीं मेकाज में कार्यरत इंटर्न, जेआर का कहना है की वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2018 के करीब 200 इंटर्न है, जबकि 50 से ऊपर जेआर है, जिन्हे दो माह से वेतन नहीं दिया गया है। ऐसे में अधिकतर इंटर्न को अपने घरों से पैसे मांगकर हॉस्टल मेस का किराया देना पड़ता है। डीन कार्यालय में मौजूद भुगतान शाखा से सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर दो माह से घुमाया जा रहा है। कई ऐसे भी इंटर्न है जो विदेश से पढ़ाई करके आने के बाद यहां अपनी सेवा दे रहे है, जिन्हे अस्पताल परिसर में रूम तक नहीं दिया गया है। मेकाज के इंटर्न ने बताया की वेतन की बात को लेकर कई बार भुगतान शाखा भी गए, लेकिन वहां भी गोल-गोल जवाब दिया जा रहा है। ऑफिस के कर्मचारी भी सही नहीं बता रहे हैं। कुछ इंटर्न व जेआर ने बताया की सबसे पहले केवल अकाउंट नंबर ही मांगा गया था, लेकिन कॉलेज की ओर से एक फॉर्म दिया गया है।

होटल में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मारा छापा

कांकेर। अगर आप परिवार, रिश्तेदरों के साथ बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान। नगर के चर्चित होटल ग्रीन पॉम में खाद्य सुरक्षा टीम को एक्सपायर समान बरामद हुआ है। जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर एक्सपायर खाद्य समाग्री परोस रहे थे।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के निर्देश में खाद्य सुरक्षा की टीम ने होटल ग्रीन पॉम एवम होटल बाफना लॉन का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान होटल ग्रीन पॉम से सूजी 10 पैकेट, लाल गुलाब बेसन 3 पैकेट, दलिया 6 पैकेट, एवरेस्ट स्नैक सॉस 1 पूड़ा एक्सपायरी पाया गया। जिसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही होटल ग्रीन पॉम से पनीर बटर मसाला का नमूना गुणवत्ता जांच के लिए लिया गया है। इसके अलावा होटल बाफना लॉन से पनीर भुजी का नमूना गुणवत्ता जांच हेतू लिया गया। आगे की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही है। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने बताया कि बाजार में बिक रही खाद्य सामग्रियों को खरीदने से पहले उपभोक्ता उनकी एक्सपायरी तारीख और बैच नंबर पर अवश्य नजर डाल लें। जिससे घटिया खाद्य सामग्री लेने से बचा जा सके। गौरतलब हो कि बाजार में धड़ल्ले से इन दिनों पैकिंग खाद्य सामग्री बिना एक्सपायरी और मूल्य दर के बिक रही हैं। जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है।

भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, सबसे गर्म रहा जांजगीर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। इस साल 2023 में फरवरी से मार्च तक भीषण गर्मी रही। कई जिलों में अधिकतम तापमान से लू की संभावना बनी रही। इस दौरान बादल छाने की वजह से तापमान में गिरावट से लू कम देखने को मिला। माना जा रहा है कि ऐसा 30 साल बाद हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान में भी बादल छाने के साथ साथ हल्की बारिश की वजह से लू नहीं लगी। बीते दिनों विभाग के एक्सपर्ट ने लू लगने का अलर्ट जारी किया था। फरवरी महीने के जाते ही गर्मी शुरू हो जाती है। सामान्यतौर पर देखा जाए तो प्रदेश में गर्मी मई तक ही रहती है।

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में एक-दो स्थानों में हल्की से माध्यम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.3 है। एक-दो दिन का उत्तरी छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर आंतरिक कर्नाटक तक पूरे तेलंगाना में औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्रदेश में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान जांजगीर जिला में 45.3 डिग्री सेल्सियस है। रायगढ़ में 44.5 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस , कोरबा में 41.1 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, मुंगेली में 42.1 डिग्री सेल्सियस, बलौदाबजार में 43. 4 डिग्री सेल्सियस, महासमुंद में 42. 2 डिग्री सेल्सियस, राजनांदगांव में 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।

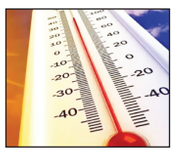

उद्योग मंत्री लखमा ने निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट का किया निरीक्षण

■ प्लांट खुलने से क्षेत्र के लोगों को मिलेगा रोजगार

रायपुर। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज कोण्डागांव जिले के ग्राम कोकोडी में निर्माणाधीन इथेनॉल प्लांट का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा की। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी प्लांट के निर्माण के प्रति उत्साहित हैं। प्लांट की निर्माण तेज गति को देखते हुए सभी आश्वश्त है कि अब उनके मक्के की फसल का उचित मूल्य प्राप्त होगा और उन्हें लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि लगभग 140 करोड़ रूपए की लागत से कोकोड़ी में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री ने इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर श्री दीपक सोनी के साथ प्लांट का भ्रमण करते हुए प्लांट निर्माण से जुड़े अधिकारियों से चर्चा कर प्रगति के संबंध में जानकारी ली, अधिकारियों ने बताया कि प्लांट का कार्य निर्माण का कार्य द्रुत गति से संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सोनी ने बताया कि प्लांट शुरू होने पर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर प्लांट में उनकी क्षमतानुसार कार्य प्रदान किया जाएगा और आस पास के ग्रामीणों को रोजगारमूलक गतिविधियों से लाभान्वित किया जायेगा।

उद्योग मंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि इस प्लांट के खुल जाने से क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सुलभ होगा। उन्होंने प्लांट में कार्यरत श्रमिकों से नियमित मजदूरी भुगतान एवं कार्य की परिस्थितियों की जानकारी दी। श्रमिकों ने बताया कि प्लांट में नियमित रूप से भुगतान हो रहा है, साथ ही अधिकारियों द्वारा कार्य में पूर्ण सहयोग दिया जाता है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा, प्लांट प्रबंध निर्देशक केएल उइके सहित प्लांट निर्माण से जुड़े एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

चेंदरू मंडावी द टाइगर बॉय की प्रतिमा का उद्योग मंत्री ने किया अनावरण

नारायणपुर। उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने नारायणपुर जिले के प्रवास के दौरान टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंदरू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण जिला मुख्यालय नारायणपुर के नया बस स्टैण्ड चौक एवं ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल में किया। उन्होंने इस मौके पर गढ़बेंगाल स्थित पार्क का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि यहां बच्चो के खेलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है।

उल्लेखनीय है कि टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंदरू मंडावी का जन्म नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़बेंगाल में हुआ था। उनकी दोस्ती बाघ (टेंबु) से होने के कारण टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध था। चेंदरू और बाघ की दोस्ती पर बनी फिल्म द जंगल सागा को 1997 में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ। स्वीडन के फिल्म निर्देशक अरने सक्सहार्फ द्वारा बनाई गई इस फिल्म से चेंदरू मंडावी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। चेंदरू स्वीडन में भी एक वर्ष रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपने गांव में ही रहे, जहां 78 वर्ष की आयु में 18 सितंबर 2013 को उनका निधन हुआ।

चेंदरू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधानसभा के विधायक श्री चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव सहित अधिकारी, कर्मचारी और चेंदरू के परिवारजन एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

किसान विरोधी है केंद्र सरकार, एमएसपी में बढ़ोतरी नाकाफी : मुख्यमंत्री

■ सीएम भूपेश बोले-गिरिराज से कोई भी कांग्रेसी कर लेगा बहस

रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ 7 प्रतिशत एमएसपी बढ़ाया है। पिछले 5 साल में जितना बढ़ाए उतना भी अभी नहीं बढ़ाए हैं। कम से कम 300 रुपए एमएसपी बढ़ाना चाहिए था। ये बढ़ोतरी नाकाफी है।

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती पर कहा कि वो किस मंच में आना चाहते हैं बताएं। हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। उनसे बहस के लिए तैयार हैं। हमारा कोई भी कार्यकर्ता उनसे बहस कर लेगा। भाजपा के 15 सालों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की ओर से मंत्रियों से रिपोर्ट कार्ड मांगने के सवाल पर कहा कि कुमारी सैलजा लगातार समीक्षा कर रही हैं। मंत्रियों और मेरे साथ भी बैठक कर चुकी हैं। उसी सिलसिले में वे जानकारियां ले रही हैं।

धर्मांतरण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के 15 सालों में सर्वाधिक चर्च बने हैं। भाजपा के 15 सालों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। इस मामले में जो भी शिकायतें हुई हैं। उस पर कार्रवाई हुई है। कुछ फर्जी शिकायतें भी हुई है। मैंने पहले भी कहा कहा है कि प्रदेश में चर्च तभी बनेंगे जब वहां उसके मानने वाले लोग रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से मोदी मित्र बनाए जाने पर कहा कि चुनाव आया है तो मोदी मित्र बना रहे हैं। मुस्लिमों को याद किया जा रहा है। इसके बाद जिहाद के नाम पर गाली देंगे।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहिए फसलों के दामों में बढ़ोतरी नाकाफी : किसान सभा

गरियाबंद। केंद्र सरकार ने बुधवार को खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए फसलों के दामों में वृद्धि किया है। इसके बाद अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा ने बढ़े दामों को नाकाफी बताया है। कहा कि, यह एक रीति की तरह है। जैसे हर साल महंगाई दर बढ़ती है, सरकार भी मजदूरी दर में वृद्धि करती है। उसी प्रकार कृषि उत्पाद के दामों में भी थोड़ी वृद्धि कर दी जाती है जो कि यह नाकाफी है। किसान सभा के सचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किसी भी फसल का लागत से डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। जो मूल्य सरकार तय करती है वह भी किसानों को उनके उपज का पूरे साल भर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके इसके लिए कोई कानूनी गारंटी दे रही है। कहा कि, फसलों की दामो में मामूली वृद्धि से किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसानों को उनके सभी फसलों के लिए 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिल सके यह कानून चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत से डेढ़ गुणा होनी चाहिए।

पीएम ने कलावती से नहीं सीखी गरीबीः गिरिराज

बघेल सरकार ने छीना गरीबों का हक, विदाई का वक्त करीब

रायपुर। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी कलावती से गरीबी नहीं सीखी, किसी ट्रक ड्राइवर से गरीबी का दर्द महसूस नहीं किया, बल्कि गरीबी में जन्म लेकर और चाय बेचकर गरीबी को जिया है। इसीलिए वे पूरे देश के लिए जीते हैं।

जगदलपुर में केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के नौ वर्षों का कार्यकाल सेवा, समर्पण और गरीबों के कल्याण की बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। केन्द्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी में जन्मे, गरीबी में पले-बढ़े, गरीबों की पीड़ा को अनुभव करते हैं और इसिलए गरीबों के कल्याण की चिंता सतत कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के महा जनसम्पर्क अभियान के सिलसिले में गुरुवार को स्थानीय टाउन क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी कलावती से गरीबी नहीं सीखी, किसी ट्रक ड्राइवर से गरीबी का दर्द महसूस नहीं किया, बल्कि गरीबी में जन्म लेकर और चाय बेचकर गरीबी को जिया है। इसीलिए वे पूरे देश के लिए जीते हैं, पूरे देश के साथ परिवार-भाव बनाकर रखते हैं। केन्द्र सरकार ने महज नौ वर्षों में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाकर गरीबों को पक्के मकान की सौगात दी। जल जीवन मिशन के तहत देशभर के 12 करोड़ परिवारों को ताजा और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया, घर-घर शौचालय बनवाकर केन्द्र सरकार ने माताओं-बहनों को खुले में शौच की शर्मिंदगी से उबारा है। ऐसे अनेक काम केन्द्र की सरकार ने किए हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों, गरीबों को ठगने का काम ही किया है। प्रधानमंत्री आवास नहीं बनाने को लेकर भी भूपेश-सरकार को गरीबों का हक छीनने वाला बताया और कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के आते ही प्रदेश के सभी गरीबों का आवास बनवाया जाएगा। हर घर में नल-जल कनेक्शन देकर साफ और ताजा जल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल पर कटाक्ष करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि न जाने वे किस स्वप्न लोक में रहते हैं। कैसे शराब में घोटाला करें, कैसे जनता की गाढ़ी कमाई लूटें। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बस यही काम हुआ है।

छत्तीसगढ़ का पैसा राहुल गांधी को सौंपने में ही मुख्यमंत्री बघेल को ज्यादा मजा आ रहा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार केन्द्र की मोदी सरकार के अच्छे कार्यों और सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। केन्द्र ने गरीबों को प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त अनाज देने की जो योजना जारी रखी है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उसे बंद करके अपनी गरीब विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विदाई वक्त अब करीब आ गया है।इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, हर घर शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से सतत् गरीबों, किसानों और सभी वर्गों के कल्याण का काम अपने नौ साल के कार्यकाल में किया है। केन्द्र सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्र सरकार ने किया है।

इसी प्रकार दुनिया में भारत का मान-सम्मान और गौरव बढ़ा है। आतंकवाद आज काबू में है। आज सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वाले देश को उसके घर में घुसकर करारा जवाब दिया है। साव ने कहा कि केन्द्र से प्रधानमंत्री मोदी जो राशि गांव-गरीब-किसानों के कल्याण के लिए भेज रहे हैं, उसे रोकने के लिए ब्रेकर का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार कर रही है।

आदिवासी पुरखौती को याद करने भाजपा की सम्मान यात्रा

रायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि प्रदेश में 9 जिन से आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का प्रारंभ होगा।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदर्शों को गांव-गांव में प्रचारित करना, लोगों के हृदय में शहीदों की सोच और भावनाओं के प्रति सम्मान एवं आभार का भाव उत्पन्न करना आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का उद्देश्य है।उन्होंने कहा कि आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा केवल कार्यक्रम नही बल्कि वक्त की जरूरत है। जिस छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखकर हमारे आदिवासी नायकों ने अपनी बलिदानी देकर अपना सर्वस्व न्योछावर किया था, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने उस छत्तीसगढ़ का सर्वनाश कर दिया है।शहीद वीर नारायण सिंह ने भूखों का पेट भरने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के सैंकड़ों करोड़ का चावल घोटाला भूपेश सरकार कर चुकी है। शहीद गुण्डाधुर और शहीद गेंद सिंह ने आदिवासी संस्कृति के लिए अपनी बलिदानी दे दी थी। भूपेश सरकार मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों की मूल संस्कृति को खत्म करने पर तुली है। प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण आज पूरे बस्तर संभाग में मूल आदिवासियों और मतांतरित आदिवासियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। संत गहिरा गुरु एवं माता राजमोहनी देवी ने सामाजिक चेतना, उत्थान और शराबबंदी के लिए अपना जीवन खपा दिया, आज भूपेश सरकार ने उसी समाज को नशा और अपराध के आगोश में झोंक दिया है। पूरे प्रदेश में शराबबंदी का वादा करके आई इस कांग्रेस सरकार ने गांव गांव में शराब बिक्री के तंत्र विकसित कर दिए हैं। सुदूर वनांचलो में आज हत्या, दुष्कर्म, भूख बेरोजगारी जैसे मामले बढ़ गए है।विकास मरकाम ने कहा कि क्या यही छत्तीसगढ़ था जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? क्या यही बस्तर था जिसके लिए शहीद गुण्डाधुर जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था।

सीम बघेल के पिता घर में गिरे अस्पताल में कराए गए भर्ती

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नन्दकुमार बघेल की तबियत अचानक खराब होने के कारण उन्हें राजधानी के मोवा स्थित श्री बालाजी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया. जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है. जानकारी अनुसार रात 12 बजे वह निवास पर गिर गए थे, जिससे उनके बांए पैर की हड्डी (नेक ऑफ फीमर बोन) फैक्चर हो गई. जिसके कारण सुबह 7 बजे उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया.

बता दें कि, श्री बालाजी सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल में सीएम भूपेश के पिता को भर्ती किया गया है. जहां मेडिसिन, अर्थो, न्यूरो सर्जरी, के डाक्टरों की टीम ने पाया की लेफट फीमर बॉन फैक्चर है. जिसकी सर्जरी करने की सलाह दी गई. जांच के बाद ऑर्थोपेडिक डाक्टरों की टीम डॉ. ल्यूनिक यदू, डॉ रमिश पठान, डॉ अमीन कुरैशी, ऐनेस्थेटिक टीम डॉ. सुनील कामरा, डॉ रीमा वाधवा, डॉ मनीष नाग, वहीं क्रिटिकल केयर की टीम डॉ प्रफुल्ल अग्निहोत्री, डॉ सोनल वाजपाई, की निगरानी में बाइपोलर मॉड्यूलर हेमीआर्थोप्लास्टी का सफलतापूर्वक आपरेशन किया गया. डॉक्टरों की टीम तकरीबन 3 घंटे तक लगी रही, जिसके बाद यह आपरेशन सफल हुआ. हॉस्पिटल में अभी नन्दकुमार बघेल को वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है.श्रीबालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमेन डॉ. देवेंन्द्र नायक ने बताया कि, सीएम बघेल के पिता नंदकुमार बघेल का बाइपोलर मॉड्यूलर हेमीआर्थोप्लास्टी आपरेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है. अभी 48 घंटे तक उन्हें वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए यह आपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा, जिसमें हमें सफलता मिली है. उनके हालत में काफी सुधार है. इस बीच स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हॉस्पिटल पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना।

सीएम चन्द्रनाहू कुर्मी समाज के सम्मेलन में होंगे शामिल

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 9 जून शुक्रवार को कबीरधाम जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कबीरधाम जिले में विकास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 140 करोड़ 50 लाख रूपए के विभिन्न विकासमूलक कार्यों की सौगात देंगे। इन सौगातों में कुल 24 अलग-अलग विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल हैं। जिसमें 6 कार्य लोकार्पण के है, जिनकी लागत 45 करोड़ 92 लाख 41 हजार रूपए और 18 कार्य शिलान्यास के है, जिनकी लागत 94 करोड़ 56 लाख 80 हजार रूपए है। मुख्यमंत्री बघेल के साथ कार्यक्रम में मोहम्मद अकबर, विधायक ममता चन्द्राकर सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बघेल 27 करोड़ 77 लाख 73 हजार की लागत से जल आवर्धन योजना, 9 करोड़ 69 लाख 56 हजार की लागत से हाईटेक बस स्टैण्ड निर्माण एवं बाह्य विकास कार्य, 53 लाख 76 हजार रूपए की लागत से पौनी पसारी योजना 2 नग, 1 करोड़ 34 लाख की लागत से कवर्धा में अग्निशमन केन्द्र कार्यालय भवन कानिर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे।

2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी अब की बार 75 पारः मोहन मरकाम

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि संभागीय सम्मेलनो से कांग्रेस की मजबूत जमीन तैयार हो रही है। अभी तक हमोर तीन संभागीय सम्मेलन बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग के हो चुके है। रायपुर और सरगुजा संभाग के बाद कांग्रेस का विधानसभावार प्रशिक्षण और संकल्प शिविर होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार के काम और जनकल्याणकारी योजनायें कांग्रेस सरकार का ब्रह्मास्त्र होगी। भाजपा के पास कांग्रेस का मुकाबला करने के लिये कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा हवाहवाई और काल्पनिक मुद्दों पर प्रदेश में राजनीति करना चाह रही जिसके कारण वह जनता से और दूर होते जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने के बाद कांग्रेस के प्रति जनता का भरोसा और बढ़ते गया, 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय

चुनाव, पंचायत चुनावों में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में हताशा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है।

मरकाम ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पास बताने के लिये अपने सरकार के गौरवशाली जनहित के काम है। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दविहीन है। इसके विपरीत कांग्रेस के पास अपनी सरकार के साढ़े चार सालों के काम की लंबी फेहरिस्त है। 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, दाई दीदी क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं से प्रदेश के आम आदमी का भरोसा कांग्रेस के प्रति बढ़ा है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि जनता, कांग्रेस सरकार बनाम भाजपा के 15 साल की तुलना कर रही है। भाजपा ने 2003 में आदिवासियों को 10 लीटर दूध वाली गाय देने का वायदा किया था, हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी का वायदा किया था, पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों से किये वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने चार साल में आदिवासी वर्ग के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के एवं कानूनी अधिकार के लिये अनेको कार्य किया। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी के वर्ग शिक्षा के लिए 300 से अधिक बंद स्कूलों को खोला गया। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा के नीतियों के तहत काम किया गया।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

धर्मांतरण को शासकीय संरक्षण मिला हुआ हैः अनुराग

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंककर प्रदेश की कांग्रेस सरकार धर्मांतरण व तुष्टीकरण के अपने राजनीतिक चरित्र के चलते छत्तीसगढ़ के सामाजिक और साम्प्रदायिक सौहार्द को तबाह करने पर तुली है। जशपुरनगर के ग्राम बालाछापर

में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का कुचक्र चलाए जाने से उत्पन्न विवाद के सामने आने के बाद श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार धर्मांतरण के घातक एजेंडे की सरपरस्त बनी हुई है। प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों को लक्षित करके ईसाई मिशनरियां जबरिया धर्मांतरण का कुचक्र चला रही हैं। जशपुरनगर के बालाछापर में जन्मदिन समारोह के नाम पर ग्रामीणों को एकत्र करके हिन्दुओं का धर्मांतरण कराए जाने की भनक लगते ही हिन्दू संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया और बाद में पुलिस ने नन सहित पांच आरोपियों पर जुर्म दर्ज किया। श्री सिंहदेव ने कहा कि हाल ही बस्तर में भी जबरिया धर्मांतरण का विरोध हुआ था जिसके बाद वातावरण उग्र हुआ। प्रदेश सरकार के सत्ता-संरक्षण में चल रहे इस कुचक्र का विरोध करने वाले आदिवासियों को ही जेलों में ठूँसकर प्रताड़ित किया गया। अब जशपुरनगर में इस तरह चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश की गई है।

किसान न्याय योजना राशि नहीं मिलने का झूठा आरोप लगा रहेः धनंजय

रायपुर । भाजपा के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किस्त किसानों को नहीं मिलने के आरोप को खारिज करते हुये प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के किसान नेता राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली

किस्त खाता में प्राप्त करने के बाद न्याय योजना की पैसा नहीं मिलने की झूठा आरोप लगाकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता को कबीरधाम के बारे में बयान देने के पहले अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से पूछ लेना चाहिये कि उनके खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे आये है या नहीं। उन्हें हकीकत पता चल जायेगा। भाजपा के प्रदेश भर के सभी नेताओं के खाते में भूपेश सरकार की योजना का पैसा गया है। 21 मई को प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों के खाता में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली 1800 करोड़ रुपए की अधिक राशि जमा करा दी गई है जो किसानों को प्राप्त हो गई है। और किसान न्याय योजना की किश्त मिलने के बाद किसान खेती किसानी में जुट गए हैं, खाद-बीज की खरीदी कर रहे हैं, खेतों की जुताई कर रहे हैं और कृषि कार्यों को संपन्न करने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में भाजपा जिसके पास मुद्दा नहीं है तो पैसा नहीं मिलने का झूठा आरोप लगाकर भाजपा राजनीति करना चाहती।

किसानों के खाते में न्याय योजना की राशि नहीं जाना शर्मनाकः संदीप शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तमाम दावों का फर्जीवाड़ा भी अब सामने आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि कबीरधाम (कवर्धा)

जिले के 1.11 लाख किसानों को 79.65 करोड़ रुपए जारी किए जाने के दावे की सच्चाई यह है कि 51 हजार किसानों के खाते में एक रुपया तक नहीं आया है! किसानों के साथ छल-कपट कर रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को फिर भी 'भरोसे का सम्मेलन' जैसी सियासी ड्रामेबाजी करने में शर्म महसूस नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और न्याय योजनाओं के नाम पर ढोल पीट रहे हैं जबकि दूसरी तरफ किसानों के साथ घोर अन्याय करके उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। कबीरधाम जिले के 1.11 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 79.65 करोड़ रुपए जारी करने के दावे का काला सच यह है कि लगभग 51 हजार किसान अब तक इस राशि से पूरी तरह वंचित हैं। परेशान किसान अब बैंक और कृषि कार्यालयों के चक्कर काटने के लिए विवश हो रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राशि जारी नहीं होने के कारण किसानों का कृषि-कार्य ठप पड़ गया है।

यूपीए सरकार के समय धान के समर्थन मूल्य में 143 प्रतिशत बढ़ा थाः शुक्ला

रायपुर। मोदी सरकार के द्वारा धान के समर्थन मूल्य में की गयी बढ़ोत्तरी ऊंट के मुंह में जीरा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार आदतन किसान विरोधी है। मोदी ने 2014 के चुनाव के पहले वायदा

किया था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी की जायेगी तथा कृषि उपज के लागत मूल्य का ज्यादा समर्थन मूल्य घोषित किया जायेगा लेकिन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशो को मानने का भरोसा दिलाने वाले मोदी ने हर साल किसानों से धोखा किया। मोदी और भाजपा किसान से दो बड़े वादे कर सत्ता में आए। पहला वादा था, किसान के समर्थन मूल्य की लागत+50 प्रतिशत मुनाफा पर निर्धारित करना। दूसरा वादा था कि इस मूल्य निर्धारण के फॉमूले से साल 2022 तक देश के 62 करोड़ किसान की आय दोगुनी हो जाना। दोनों बातें सफेद झूठ साबित हुई है। किसान साल दर साल ठगे जाते रहे।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ मोदी सरकार लगातार धोखेबाजी कर रही है। यूपीए सरकार के 10 सालों में धान के समर्थन मूल्य में 142.85 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गयी थी। जब मनमोहन सरकार बनी तब धान का समर्थन मूल्य 560 रू. था, मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार में धान का समर्थन मूल्य बढ़कर 1360 रू. हो गया था।

संजय अलंग का बनारस हिन्दू विवि में देंगे व्याख्यान

रायपुर। संजय अलंग छत्तीसगढ़ के इतिहास और संस्कृति के विषय विशेषज्ञ के रूप में 10 जून को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे।बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग,काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश हिन्दी, संस्थान एवं भारतीय दर्शन परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठी में संजय अलंग का व्याख्यान छत्तीसगढ़ से संबंधित विषय पर है। संजय अलंग छत्तीसगढ़ पर गहन शोध परक कार्य और पुस्तकों के लिए स्थापित व प्रसिद्ध लेखक और विद्वान हैं। उनको छत्तीसगढ़ पर शोध के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सर्वश्रेष्ठ शोध लेखन का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति पुस्तक को एक लाख रुपये का सर्वश्रेष्ठ शोध लेखन का सर्वोच्च सम्मान मिला था। छत्तीसगढ़ पर संजय अलंग की दस से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं।इन पुस्तकों में छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति के अलावा छत्तीसगढ़ की रियासतें और ज़मींदारियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और जातियाँ आदि जैसी कई सुविख्यात पुस्तकें सम्मिलित हैं।संजय अलंग के तीन कविता संग्रह भी प्रकाशित हैं और उन्हें भी सम्मानित किया गया है।

रीपा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती

- राजस्थान की कम्पनी ने सामग्रियों की गुणवत्ता को सराहा और एमओयू में रूचि दिखाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर अग्रसर हैं। रीपा के तहत विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं और युवाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार व स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने मुंगेली जिले के प्रत्येक विकासखंड के दो-दो रीपा का निर्माण किया गया है। जिसका अब अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है।

रीपा द्वारा उत्पादित सामग्रियों का क्रय करने अब अन्य राज्य के निजी कम्पनी भी

रूचि दिखा रहे हैं। बता दें कि पथरिया विकासखंड के ग्राम धरदेई में शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत रीपा का निर्माण किया गया है। जहां श्री विष्णु बहुद्देशीय सहकारी समिति द्वारा आर. ओ. वाटर, चिक्की, पीनट एवं मिक्चर व आर्टिफिशियल ज्वेलरी का उत्पादन कार्य शुरू किया गया है। जिसका विगत दिनों राजस्थान की स्वीट्स कम्पनी की शाखा बिलासपुर की टीम ने अवलोकन किया और सामग्रियों की गुणवत्ता देखकर सराहना की। साथ ही सामग्रियों का क्रय व प्रशिक्षण हेतु ओएमयू करने में रूचि भी दिखाई।

ग्राम धरदेई के रीपा में कार्यरत समूह की अध्यक्ष श्रीमती मधु बरगाह ने बताया कि नगर पंचायत सरगांव में 25 मार्च को आयोजित ''भरोसे का सम्मेलन'' कार्यक्रम में हमने 230 लीटर आरओ वाटर की बिक्री 3600 रूपए में की थी। अब तक रीपा में 4800 लीटर आर ओ वाटर का उत्पादन तथा 3200 लीटर आर. ओ. वाटर की बिक्री की जा चकी है। उन्होंने बताया कि उनके समूह द्वारा रीपा में किए जा रहे विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियों से अब तक 41 हजार 775 रूपए की आमदनी हुई है। इससे सभी महिलाएं काफी उत्साहित हैं। रीपा परिसर में सामुदायिक बाड़ी में विभिन्न प्रकार की सब्जी का उत्पादन एवं विक्रय किया जा रहा है।

छात्रावास-आश्रमों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों के अधीक्षकों के लिए ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा रायपुर तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण 10 जून तक दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण छात्रावास-आश्रमों के सुचारू संचालन के लिए दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम चरण में आज 56 छात्रावास अधीक्षक एवं 14 सहायक संचालकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभाग द्वारा प्रदेश में 3294 छात्रावास-आश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 2774 अनुसूचित जनजाति, 483 अनुसूचित जाति एवं 37 अन्य पिछड़ा वर्ग के है। प्री-मैट्रिक छात्रावास-आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को वर्तमान में 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति प्रदान की जा रही है। सरकार की घोषणा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष से इस शिष्यवृत्ति को बढ़ाकर 1500 रूपए प्रतिमाह किए जाने का बजट प्रावधान किया

गया है। प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को सम्बोधित करते हुए अपर संचालक श्री जितेन्द्र गुप्ता ने कार्यशाला का महत्व बताते हुए कहा कि माता-पिता बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चों को छात्रावास, आश्रमों में प्रवेश करवाते हैं, अतः छात्रावास अधीक्षकों को उन्हें बेहतर अनुशासन के साथ-साथ सभी आधारभूत सुविधाएं पूरी कर्तव्यनिष्ठता से उपलब्ध करवानी चाहिए। बच्चों में स्वच्छता की आदतें विकसित करना, संस्था में साफ-सुथरा रसोई घर, पौष्टिक भोजन, शौचालय की साफ-सफाई, संस्था में बिजली-पानी का मितव्ययी उपयोग आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.